

हरिभूमि

छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, हरियाणा व दिल्ली से एक साथ प्रकाशित

समाचार ही नहीं, विचार भी

haribhoomi.com

बिलासपुर, मंगलवार 22 सितंबर 2026

FOR THE FIRST TIME IN THE
HISTORY OF CHHATTISGARH



SAHELI
AURUM

PURE & PROMISING FOREVER

— A SUNIL JAIN LEGACY —

presents

BIGGEST
JEWELLERY
SHOW
2026

21st TO 25th
SEPTEMBER

11 AM TO
9 PM

Launch Date - 22nd September

Time - 11:00 AM

Venue - Sadar Bazar, Raipur

आमंत्रित अतिथियों के गरिमामयी उपस्थिति में



आदरणीया श्रीमति कौशल्या देवीजी साय
समाज सेविका
धर्मपत्नी श्री विष्णुदेव जी साय मुख्यमंत्री, छ.ग.



आदरणीया श्रीमति मीनल चौबे जी
महापौर (प्रथम नागरिक)
नगर निगम, रायपुर, छ.ग.

Launching 11 New Collection in the Presence of Our Esteemed Guests

ROYALIS
Timeless Heritage Art

EKĀM
THE LIMITED MASTERPIECES

ETERN
MAGIC OF
HANDCRAFT DIAMONDS

Glint
THE DIAMONDS
GLAM

Rajsa
The Royal Touch

Nia
ITS LITE IT'S
A DELIGHT

SHUBH RATNA
THE RIGHT GEMSTONE

Riva
Polki Classics

Bomat
THE ANTIQUE
ARTISTRY

Rosette
ROSE GOLD AFFAIR

inara
OPEN POLKI ELEGANCE

SADAR BAZAR, RAIPUR
+91 9584411144

SHREE SHIVAM MALL, DURG
+91 9244509870

BAZAR CHOWK, UTAI
+91 7647072145



छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, हरियाणा व दिल्ली से एक साथ प्रकाशित

वन अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र में लगाए जाएंगे विलुप्त प्रजाति के औषधीय पौधे

हरिभूमि न्यूज ►► रायपुर

राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र के 21 हेक्टेयर में लगे 20 हजार से ज्यादा सूबबुल पेड़ों को काटा जाएगा। इसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। काटे गए पेड़ों की जगह विलुप्त प्रजाति के औषधीय तथा छायादार पेड़ लगाए जाने की तैयारी की जाएगी। संस्थान के संचालक कौशलेंद्र कुमार का कहना है, पेड़ों की कटाई के बाद जड़ों को भी नष्ट किया ►►शेष पेज 4 पर



63 हेक्टेयर में फैला है संस्थान

राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना वर्ष 2007 में हुई थी। संस्थान का पूरा परिसर करीब 63 हेक्टेयर में फैला है। यहां वन अनुसंधान, प्रशिक्षण और वन प्रबंधन से जुड़े विभिन्न कार्य किए जाते हैं। अब परिसर के एक बड़े हिस्से में फैले सूबबुल को हटाकर स्थानीय वनस्पतियों के पुनर्विकास के लिए जगह तैयार किया जाएगा।



पेड़ काटने टेंडर जारी

औषधीय पौधे लगाए जाएंगे

वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र में 21 हेक्टेयर में फैल चुके सूबबुल के पेड़ों की कटाई करने टेंडर जारी किया गया है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद पेड़ों की कटाई की जाएगी। साथ ही जमीन के अंदर जड़ों को भी नष्ट किया जाएगा। खाली जमीन में विलुप्त प्रजाति के तथा स्थानीय फलदार तथा छायादार पौधों का रोपण किया जाएगा। - कौशलेंद्र कुमार, संचालक राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

सोने का सच्चा भाव

आनंद का सच्चा भाव

18 कैरेट रेड (75.00%)	₹115439/-
22 कैरेट रेड (91.60%)	₹140990/-
24 कैरेट रेड (99.99%)	₹153904/-

Live Rate अरुंद ज्योत्स के सोलवेल पर पर चेक करें

anand jewelrys

Pandri, Raipur

जड़ें गहराई तक जाकर पानी सोखती हैं

वनस्पति के जानकारों के अनुसार सूबबुल के पेड़ मिट्टी को जितना उपजाऊ बनाता है, उतनी ही गहराई में जाकर इनकी जड़ें पानी सोखती हैं, इस कारण भू-जल का स्तर तेजी से कम होने लगता है। सूबबुल एक फलीदार पौधा है। इसकी जड़ों में विशेष ग्रंथियां होती हैं जो हवा से नाइट्रोजन लेकर उसे मिट्टी में स्थिर करती हैं। इससे बिना रासायनिक खाद (यूरिया) के ही मिट्टी की उर्वरता प्राकृतिक रूप से बढ़ जाती है। इसकी पत्तियां नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम से भरपूर होती हैं। जब इसकी पत्तियां झड़कर मिट्टी में सड़ती हैं, तो वे बेहतररीन कमपोस्ट या हरी खाद का काम करती हैं। यह खराब, अम्लीय या कम उपजाऊ मिट्टी में भी आसानी से उग जाता है और धीरे-धीरे उस जमीन को खेती योग्य बनाने में मदद करता है।



हरिभूमि न्यूज ►► नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को बताया गया कि अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच कर रही अदालत द्वारा गठित विशेष जांच टीम 25 सितंबर तक या उससे पहले पहला आरोपपत्र दाखिल करेगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ को बताया कि इस मामले में पहली गिरफ्तारी के बाद से कानूनी तौर पर तय 90 दिन की समय-सीमा जल्द ही खत्म होने वाली है। मेहता ने कहा, पहली गिरफ्तारी की तारीख से 90 दिन की अवधि 25 सितंबर को पूरी हो जाएगी, इसलिए हमें आरोपपत्र दाखिल करना होगा, अन्यथा उन्हें (आरोपियों को) डिफॉल्ट जमानत मिल जाएगी। शीर्ष अदालत ने सीलबंद लिफाफे में एसआईटी की ओर से दाखिल की गई विस्तृत वस्तु स्थिति रिपोर्ट का भी अवलोकन ►►शेष पेज 4 पर

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, एसआईटी 25 सितंबर तक दाखिल करेगी आरोपपत्र

राम मंदिर में 105 बार चढ़ावा की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई घटनाएं

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच अब अहम मोड़ पर पहुंच गई है। यूपी सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एसआईटी दो दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करेगी। एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया है कि सीसीटीवी फुटेज की जांच के दौरान चढ़ावे की चोरी से जुड़ी 105 घटनाओं की पहचान की गई है। ऐसे में अब चार्जशीट के जरिए जांच से जुड़ी विस्तृत जानकारी सामने आने की उम्मीद है।

एसआईटी रिपोर्ट में खुलासा

एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक, जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। इसी फुटेज के आधार पर चढ़ावे की चोरी से जुड़ी 105 घटनाओं की पहचान की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन घटनाओं की जांच पूरी हो चुकी है। एसआईटी के अनुसार अब जांच का अगला चरण चार्जशीट दाखिल करना है। हालांकि, इन 105 घटनाओं में कितनी रकम की चोरी हुई या किन लोगों की भूमिका सामने आई, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। इन विवरणों का खुलासा चार्जशीट में होने की बात कही गई है।



किस मामले की सुनवाई हुई?

सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच को लेकर दाखिल कई याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इन याचिकाओं में स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने एसआईटी की जांच की स्थिति अदालत के सामने रखी। पीठ ने एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट भी देखी। अब दो दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल होने के बाद मामले की जांच में सामने आए तथ्यों और आरोपों की विस्तृत तस्वीर सामने आने की उम्मीद है।

इधर, मिश्र ने राम मंदिर न्यास के सीईओ का पदभार संभाला

अयोध्या सेवाविभूत एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्र ने अयोध्या में राम मंदिर का प्रबंधन करने वाले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में सोमवार को औपचारिक तौर पर पदभार ग्रहण कर लिया। रविवार को अयोध्या पहुंचे मिश्र ने रात रामकोट क्षेत्र स्थित तीर्थ क्षेत्र भवन में ठहरे। चढ़ावा चोरी के आरोपों के बीच प्रशासनिक पुनर्गठन के तहत 62 वर्षीय मिश्र को दो सितंबर को न्यास का प्रथम सीईओ नियुक्त किया गया था। मिश्र का चयन कई चरण की प्रक्रिया के बाद किया गया।

सोमवार सुबह राम मंदिर में पूजा-अर्चना की, जिसके बाद वह पदभार ग्रहण करने मंदिर परिसर में नवनिर्मित कार्यालय पहुंचे। मिश्र अयोध्या पहुंचने के बाद रविवार रात रामकोट क्षेत्र स्थित तीर्थ क्षेत्र भवन में ठहरे। चढ़ावा चोरी के आरोपों के बीच प्रशासनिक पुनर्गठन के तहत 62 वर्षीय मिश्र को दो सितंबर को न्यास का प्रथम सीईओ नियुक्त किया गया था। मिश्र का चयन कई चरण की प्रक्रिया के बाद किया गया।

बंद जीएसटी नंबरों से करोड़ों का कारोबार एआई टूल्स और डेटा एनालिटिक्स से पहचान, 3000 कारोबारियों को नोटिस



हरिभूमि न्यूज ►► बिलासपुर

प्रदेश में बंद जीएसटी नंबरों से करोड़ों रुपए का कारोबार किया जा रहा है। बिलासपुर, रायपुर समेत प्रदेश भर में करीब तीन हजार ऐसे बड़े का रो बा रि यों, संस्थानों और फर्मों की पहचान की गई है, जो अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसिल कराने के बावजूद उसी अवैध नंबर का इस्तेमाल कर बेखोफ करोड़ों का कारोबार ►►शेष पेज 4 पर



कंस्ट्रक्शन कंपनियां, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स, सीजनल सामान विक्रेता, इलेक्ट्रिकल उपकरण और फर्नीचर कारोबारी

जांच के बाद बड़ी संख्या में जीएसटी नंबर रद्द, कई मामलों में नोटिस जारी कर एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू

फर्जी दस्तावेजों से फर्म बनाने का आरोप

जीएसटी विभाग के अनुसार जांच में कई फर्मों के पते पर कारोबार नहीं मिला। कुछ किरयानामों में संबंधित लोगों के हस्ताक्षर भी फर्जी पाए गए। वहीं फर्मों के नाम पर दर्ज बैंक खातों को भी संबंधित लोगों ने अपना नहीं बताया। विभाग ने इससे फर्जी दस्तावेजों के जरिये कारोबार दिखाकर टैक्स का लाभ लेने का मामला माना है। पुलिस ने भी कई मामलों में अपराध दर्ज किया है। अधिकारियों के अनुसार आने वाले समय में विभाग द्वारा और अधिक सदिग्ध जीएसटी खातों की जांच तथा डिजिटल निगरानी का दायरा बढ़ाया जाएगा।

खबर संक्षेप

दिल्ली हाईकोर्ट को मिले सात नए जस्टिस

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट में सात न्यायिक अधिकारियों ने न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली, जिससे संख्या बढ़कर 50 हो गई है। मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय ने न्यायमूर्ति निवेदिता अनिल शर्मा, न्यायमूर्ति निशा सहाय सक्सेना, न्यायमूर्ति संजय शर्मा, न्यायमूर्ति भरत पाराशर, न्यायमूर्ति अदिति चौधरी, न्यायमूर्ति दिनेश भट्ट और न्यायमूर्ति अरुण भारद्वाज को शपथ दिलाई।

तालाब में नहाने गए छह बच्चों की मौत

भागलपुर। बिहार के भागलपुर जिले में कर्मा-धर्मा पर्व के अवसर पर सोमवार को तालाब में स्नान के दौरान तीन लड़कियों समेत छह बच्चों की डूबने से मौत हो गई। यह हादसा सुबह करीब 10:30 बजे सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के तैरता बहियार स्थित एक तालाब में हुआ, जहां बच्चे कर्मा-धर्मा पर्व पर अनुष्ठानिक स्नान करने गए थे।

बायोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया को दी मंजूरी

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि केंद्र ने 'बायोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया' को मंजूरी दी है। इसके तहत इंडियन फार्माकोपिया कमीशन अंग और ऊतक प्रत्यारोपण में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और जैविक उत्पादों से जुड़े दुष्प्रभावों की निगरानी के लिए काम करेगा। अंग और ऊतक दाताओं एवं प्राप्त-कर्तओं, दोनों को दी जाने वाली दवाओं सामग्रियों को शामिल किया जाएगा।

एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक का इंतजार

सुचिका ने रचा इतिहास, भारत को मिले अब तक छह पदक

एजेंसी ►► नागोया

भारत का एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने का इंतजार सोमवार को भी खत्म नहीं हो पाया लेकिन निशानेबाजी रेंज पर उसने कुछ पदक बटोरे। दो दिन में भारत को कुल छह पदक मिले हैं। मिश्रित मार्शल आर्ट्स (एमएमए) में देश का पहला पोडियम फिनिश इतिहास से ज्यादा दिल तोड़ने वाली कहानी बनकर रह गया। सुचिका तारियाल सुबह कराए गए वजन में सिंगापुर की हुई हून तेओ से सिर्फ 700 ग्राम अधिक वजन होने के कारण फाइनल में जगह बनाने से चूक गई। सेमीफाइनल का यह मुकाबला बराबरी पर ►►शेष पेज 4 पर



शूटिंग में अब तक जीते पदक

10 मीटर एयर राइफल महिला व्यक्तिगत स्पर्धा : इलावेजिल व्लादिरवान (सिल्वर)
10 मीटर एयर राइफल महिला टीम स्पर्धा : सिल्वर
10 मीटर एयर राइफल मैन टीम स्पर्धा : सिल्वर
10 मीटर एयर राइफल मैन व्यक्तिगत स्पर्धा : हिमांशु दिल्ली (सिल्वर)
10 मीटर एयर राइफल मैन व्यक्तिगत स्पर्धा : रुद्राक्ष पाटिल (बronze)

नगांव उपचुनाव : प्रचार के दौरान भाजपा और कांग्रेस के बीच झड़प

भूपेश-गोगोई के काफिले पर हमला, वापस जाओ के नारे

नगांव। असम के नगांव लोकसभा उपचुनाव में प्रचार के दौरान सोमवार को समागुरी विधानसभा क्षेत्र के बारामा बाजार में कांग्रेस और भाजपा समर्थकों के बीच झड़प हुई। पुलिस के अनुसार यह घटना शाम करीब चार बजे समागुरी विधानसभा क्षेत्र में हुई, जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक समूह जनसभा के लिए लारीमुख जा रहा था। इस काफिले में धुबरी के सांसद रकीबुल हुसैन, छत्तीसगढ़ के पूर्व

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पार्टी उम्मीदवार सिबमोनी बोरा आदि भी शामिल थे। पुलिस ने बताया कि कांग्रेस नेताओं को काले झंडे दिखाने के लिए भाजपा समर्थक रास्ते में एकत्र थे। एक अधिकारी ने कहा, जब दोपहिया वाहनों पर सवार करीब 30 से 40 कांग्रेस कार्यकर्ता उस इलाके से गुजरे, तो 'गौरव गोगोई वापस जाओ, कांग्रेस वापस जाओ, रकीबुल वापस जाओ' जैसे नारे लगाए गए, जिससे तनाव पैदा हो गया।

दशहरा, दीपावली और शीतकालीन छुट्टियां 5-5 दिनों की

हरिभूमि न्यूज ►► रायपुर

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मौजूदा शैक्षणिक सत्र के लिए दशहरा, दीपावली और शीतकालीन छुट्टियों की तिथि घोषित कर दी गई है। दशहरा व दीपावली के लिए पांच-पांच दिनों की छुट्टियां प्रदान की जाएंगी। वहीं शीतकालीन छुट्टियां भी पांच दिनों की ही प्रदान की जाएगी। शासकीय विद्यालयों के साथ-साथ निजी विद्यालयों में भी इन तिथियों में अवकाश रहेगा। डीएलएड व बीएड महाविद्यालय ►►शेष पेज 4 पर



अवकाश तिथि
दशहरा - 17 से 21 अक्टूबर
दीपावली - 6 से 10 नवंबर
शीतकालीन अवकाश - 24 से 28 दिसंबर

कार की टक्कर, दो मासूमों की गई जान, पिता गंभीर

हरिभूमि न्यूज ►► डौंडीलोहारा

देवरी थाना क्षेत्र के परसुली गांव के पास रविवार रात डौंडीलोहारा-राजनांदागांव मुख्य मार्ग पर हुए सड़क हादसे में दो मासूम गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे में बाइक चालक पवन कुमार सोनकर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें रायपुर रेफर किया गया है। घटना के बाद से परसुली गांव में मातम पसरा हुआ है। परसुली निवासी पवन कुमार सोनकर रविवार रात अपने 3 वर्षीय



पुत्र हिमांशु सोनकर और 12 वर्षीय भतीजे नमन कुमार सोनकर के साथ बाइक क्रमांक सीजी 24 एस 1107 से घर के पास सड़क पर निकले थे। इसी दौरान डौंडीलोहारा की ओर से देवरी की तरफ जा रही कार क्रमांक सीजी 7360 के चालक ने तेज रफतार में वाहन को रॉन् साइड में ले जाकर बाइक को सामने से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वे गिर गए। हादसे के बाद आसपास के ग्रामीण तत्काल मौके पर पहुंचे और घायलों को संभालते हुए पुलिस तथा एंबुलेंस को सूचना दी। तीनों घायलों को देवरीबंगला ►►शेष पेज 4 पर



चालक हुआ फरार

हादसे के बाद चालक और उसके साथ मौजूद एक अन्य व्यक्ति कार को मौके पर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने वाहन को अपने कब्जे में लेकर उसके नंबर के आधार पर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। प्रत्यक्षदर्शियों और गांधीनों ने चालक के शराब के नशे में होने की बात कही है। हालांकि इसकी पुष्टि पुलिस जांच और मेडिकल जांच के बाद ही हो सकेगी। पोस्टमार्टम के बाद सोमवार को सुबह दोनों बच्चों हिमांशु और नमन का अंतिम संस्कार गांव के श्मशान घाट में किया गया।

बिन्दानवागढ़ सातधार मार्ग पर आवागमन बाधित होने से एंबुलेंस भी नहीं पहुंच पा रही गांव तक

50 लाख का रपटा टूटा, दर्जनों गांवों का संपर्क कटा

हरिभूमि न्यूज ►► नैनपुर

गरियाबंद जिले के बिन्दानवागढ़ सातधार मार्ग पर रपटा पुल बारिश के कारण ढह जाने से दर्जनों गांवों का संबंध कट गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लगभग 18 वर्ष पूर्व करीब 50 लाख की लागत से बनाया गया था। रपटा पुल के क्षतिग्रस्त होने से रोजाना स्कूल जाने वाले छात्र-छात्राओं और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी के तेज बहाव और टूटे हुए रास्ते के कारण लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को ►►शेष पेज 4 पर



आवागमन पूरी तरह बंद: कार्यपालन अभियंता

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना गरियाबंद के कार्यपालन अभियंता राहुल चंद्राकर ने बताया यह रपटा बारिश में धंस गया आवागमन पूरी तरह बंद है। दोनों तरफ जिला प्रशासन के नाम से चेतावनी बोर्ड भी लगा दिया गया है। पुल रपटा का निमाण विभाग ग्राम पंचायत द्वारा किया गया था, यह फाइल देखकर ही बता पाऊंगा।



क्षतिग्रस्त होने की दी थी सूचना, पर नहीं दिया गया ध्यान: सरपंच

ग्राम पंचायत पतौरा के सरपंच कुष्णकुमार नाग ने बताया इस पुल का निर्माण लगभग 18 वर्ष पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क विभाग द्वारा 50 लाख से अधिक की लागत से बनाया गया था। पुल धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो रहा था जिसकी शिकायत करने के बावजूद विभाग द्वारा सुधार नहीं किया गया। लगातार बारिश में एक सप्ताह पूर्व यह पुल धस गया, जिससे इस क्षेत्र के दर्जनों ग्राम, पारोटोला के हजारों लोगों का आवागमन अवरूद्ध हो गया है। यहां बड़े पुत्र निर्माण की आवश्यकता है।

चिंतन

नकल रोकना अपराध नहीं पर छात्रों को बचाना जरूरी

आईआईटी बॉम्बे में एक छात्र की आत्महत्या ने देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था के सामने ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनसे आंखें चुराना अब संभव नहीं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि एक छात्र परीक्षा में मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए क्यों पकड़ा गया और उसके बाद उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था ने बच्चों को केवल सफल होना सिखाया है, असफलता को स्वीकार करना नहीं? और दूसरा सवाल इससे भी ज्यादा सीधा है, अगर कोई शिक्षक परीक्षा में नकल रोकता है तो आखिर उसकी गलती क्या है? परीक्षा कक्ष में नियम लागू करना शिक्षक की जिम्मेदारी है। यदि किसी विद्यार्थी के पास मोबाइल पाया जाता है या वह अनुचित तरीके से उत्तर हासिल करने का प्रयास करता है तो शिक्षक का उसे रोकना स्वाभाविक है। आईआईटी बॉम्बे के मामले में संस्थान का कहना है कि छात्र को परीक्षा के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल करते पाया गया था और उसके खिलाफ तत्काल कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी। संस्थान के अनुसार शिक्षक और विभागाध्यक्ष ने उससे बात की थी और उसे यह भरोसा दिलाया गया था कि इस घटना का उसके करियर पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। इसके बावजूद छात्र की आत्महत्या ने पूरे कैंपस को हिला दिया। घटना के बाद सैकड़ों छात्र विरोध में उतर आए और परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ीं। यहां एक बेहद महत्वपूर्ण अंतर को समझना होगा। किसी शिक्षक द्वारा नकल पकड़ना एक बात है और उसके व्यवहार में अनुचितता का आरोप दूसरी बात। यदि शिक्षक ने छात्र के साथ अपमानजनक व्यवहार किया, जातिगत टिप्पणी की, अनावश्यक दबाव बनाया या नियमों से हटकर व्यवहार किया, तो उसकी जांच होनी चाहिए। परिवार ने ऐसे आरोप लगाए हैं और संस्थान ने जातिगत भेदभाव के आरोपों से इनकार किया है। इन आरोपों का फैसला जांच के आधार पर होना चाहिए, भीड़ या भावनाओं के आधार पर नहीं। लेकिन इस पूरी बहस में एक खतरनाक संदेश नहीं जाना चाहिए कि किसी विद्यार्थी को नकल करते पकड़ना ही शिक्षक की गलती है। लेकिन यहीं से कहानी का दूसरा और अधिक गंभीर पक्ष सामने आता है। आखिर इतनी छोटी असफलता इतनी बड़ी क्यों बन रही है? एक परीक्षा में पकड़ा जाना, एक विषय में फेल होना, कम अंक आना या किसी नियम का उल्लंघन करना। ये जीवन की कठिन परिस्थितियां हो सकती हैं, लेकिन जीवन का अंत नहीं। शिक्षा व्यवस्था को अपना नजरिया बदलना होगा। काउंसिलिंग केवल उस समय नहीं होनी चाहिए जब कोई विद्यार्थी संकट में पहुंच जाए। निर्णमित मानसिक स्वास्थ्य काउंसिलिंग को शिक्षा व्यवस्था का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाना चाहिए। आईआईटी बॉम्बे सहित कई उच्च शिक्षण संस्थानों में काउंसिलिंग और वेलनेस की व्यवस्थाएं पहले से मौजूद हैं। लेकिन अब जरूरत इन सेवाओं को नियमित छात्र-जीवन का हिस्सा बनाने की है। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि मानसिक स्वास्थ्य के नाम पर अनुशासन खत्म कर दिया जाए। नकल को नकल ही कहा जाना चाहिए। नियम तोड़ने पर उचित कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई और अपमान में फर्क है। अनुशासन और प्रताड़ना में अंतर है। गलती बताते और विद्यार्थी को तोड़ देने में भी फर्क है। शिक्षक का काम नियम लागू करना है। संस्थान का काम नियमों के साथ निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करना है।

विचार दयालदास बघेल



हर गरीब की थाली, हर घर की गरिमा और हर हाथ का योगदान ही है सेवा से संकल्प

भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में कुछ अवसर केवल उत्सव के नहीं होते, वे आत्मचिंतन और संकल्प के अवसर बना जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में सेवा के 25 वर्ष पूर्ण होना ऐसा ही अवसर है। यह 25 वर्ष केवल एक राजनीतिक यात्रा के वर्ष नहीं हैं, बल्कि सेवा, जनमार्गदर्शी और अंतिम पवित्र में खड़े व्यक्ति तक विकास का लाम पहुंचाने की निरंतर कोशिशों की यात्रा के रूप में देखे जाते हैं। 'सेवा संकल्प अभियान' इसी भावना को जन-जन तक पहुंचाने और विकसित भारत के निर्माण में प्रत्येक नागरिक की अपनी भूमिका को रेखांकित करने का अवसर है।

सेवा का अर्थ केवल किसी जन्मरतमंद को सहायता देना नहीं है। सेवा वह भाव है, जिसमें हम अपने आपसापस की समस्या को अपनी समस्या मानकर उसके समाधान के लिए आगे आते हैं। स्वच्छता के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी जनमार्गदर्शी की भावना को राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप दिया। वर्ष 2014 में प्रारंभ हुआ स्वच्छ भारत मिशन धीरे-धीरे सरकार की कार्यक्रम से आगे बढ़कर नागरिक सहभागिता का व्यापक अभियान बना। आज 'स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत' की भावना इसी निरंतर यात्रा को आगे बढ़ा रही है।

गंगा केवल एक नदी नहीं, भारत की आस्था, संस्कृति और सभ्यता की जीवनधारा है। नमामि गंगे के माध्यम से गंगा की स्वच्छता, घाटों के विकास, प्रदूषण नियंत्रण और जनमार्गदर्शी का एक व्यापक मिशन से जोड़ा गया। गंगा स्वच्छता पखवाड़ा, श्रमदान, घाटों की सफाई और जनसंगठकता जैसे प्रयासों ने यह संदेश दिया कि नदियों की निर्मलता केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है।

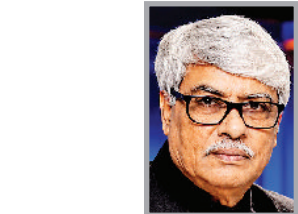
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा भाव का एक महत्वपूर्ण पक्ष गरीब और वंचित परिवारों की गरिमा से जुड़ा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने गरीब परिवारों की महिलाओं को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा हस्तक्षेप किया। 10 सितंबर 2026 तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 10.56 करोड़ से अधिक कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। यह केवल गैस कनेक्शन का आंकड़ा नहीं है, एक गरीब महिला के लिए धुएँ से राहत, समय की बचत और सम्मान के साथ जीवन जीने की सुविधा भी है। खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में भी गरीब परिवारों की हिता को केंद्र में रखा गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 1 जनवरी 2024 से पांच वर्षों के लिए लगभग 81.35 करोड़ लोगों को नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में लगभग 80 करोड़ लोग इस व्यवस्था के माध्यम से नि:शुल्क खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं। मेरे लिए, खाद्य विभाग से जुड़े दायित्व के कारण, इस सेवा का अर्थ और भी गहरा है- किसी गरीब परिवार की रसोई में चूल्हा जलना और उसकी थाली में भोजन पहुंचना शासन की संवेदनशीलता का सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण है।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मोदी की गारंटी के तहत किसानों से अधिकतम 21 किंटन प्रति एकड़ की सीमा में 3100 रुपए प्रति किंटन के मान से राज्य के 25.24 लाख किसानों से 2740 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 141.04 लाख से टन धान की खरीदी की गई है। किसानों से धान खरीदी की राशि ऑनलाईन उनके खाते में यथाशीघ्र अंतरित की गई है। किसानों को समर्थन मूल्य एवं कृषक उन्नति योजना अंतर्गत कुल 43723 करोड़ रुपए अंतरित किया गया है। आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में किसानों की सुविधा के लिए नवीन 362 उपार्जन केन्द्र खोला गया है।

छत्तीसगढ़ ने भी इस भावना को अपनी धरती और परिस्थितियों के अनुरूप आगे बढ़ाया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राज्य में 83 लाख से अधिक राशन कार्ड के माध्यम से पात्र परिवारों तक खाद्यान्न पहुंचाने की व्यवस्था है। खाद्य विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर राशनकार्ड, उचित मूल्य दुकानों और हितवाधियों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध है, जिससे खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने का प्रयास स्पष्ट होता है। बस्तर जैसे दूरस्थ अंचलों में सेवा का अर्थ और व्यापक हो जाता है। निर्याद नेल्लानार योजना के अंतर्गत दूरस्थ गांवों और जनजातीय परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जोड़ने का प्रयास इस बात का उदाहरण है कि विकास का अर्थ तभी सार्थक है, जब सुविधा उस व्यक्ति तक पहुंचे, जिसके घर तक पहुंचना सबसे कठिन है। खाद्य विभाग के आधिकारिक अभियंत्रणों में निर्याद नेल्लानार क्षेत्र के गांवों में अंत्योदय सहित विभिन्न राशनकार्डधारियों को दर्ज किया गया है।

हमारे लिए 'सेवा भरो योगदान' केवल एक अभियान का नारा नहीं, बल्कि विकसित भारत के निर्माण का नागरिक संकल्प है। कोई व्यक्ति रक्तदान करके सेवा कर सकता है, कोई नदी-घाट की सफाई में श्रमदान करके, कोई गरीब परिवार को सरकार योजना का लाभ दिलाकर, कोई जन्मरतमंद तक राशन पहुंचाने में सहयोग देकर और कोई अपने गांव-मोहल्ले को स्वच्छ रखने का संकल्प लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने पर छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से मेरा यही भाव है कि सेवा की यह यात्रा जनमार्गदर्शी की गई उर्ज में बदले। विकसित भारत का संकल्प तभी पूर्ण होगा, जब विकास का प्रकाश अंतिम व्यक्ति के घर तक पहुंचे, जब किसी गरीब की थाली खाली न रहे, जब किसी महिला को धुएँ में जीवन बिताना पड़े, जब गांव स्वच्छ हों, नदियां निर्मल हों और हर नागरिक यह कह सके - 'राष्ट्र निर्माण में मेरा भी योगदान है।' यही सेवा है। यही संकल्प है। और यही विकसित भारत की ओर बढ़ते छत्तीसगढ़ का जन-जन का योगदान है।

लेखक: मंत्री खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोग संरक्षण विभाग अन्न शासन



सियासत आमकार चौधरी

राहुल गांधी के “वोट चोरी, सरकार चोरी और अब पार्टी चोरी” वाले आरोप ने तृणमूल कांग्रेस के नाम–चिहन विवाद को व्यापक राजनीतिक बहस में बदल दिया है। चुनाव आयोग का कहना है कि दो प्रतिद्वंद्वी गुटों के दावों के कारण अंतिम निर्णय तक मूल नाम और चिहन पर रोक लगाई गई है। लेकिन इस बहस को केवल मौजूदा विवाद तक सीमित रखना इतिहास को अधूरा पढ़ना होगा। भारतीय राजनीति में दलों का विभाजन, समर्थन वापसी, गठबंधन और अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल लंबे समय से सता–संघर्ष का हिस्सा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस समेत सभी दलों के अतीत को तथ्यों की कसौटी पर परखना जरूरी है।

यह मन का कमाल है



संकलित दर्शन



करंट अफेयर

अत्यधिक मजबूत प्रतिरक्षा के बावजूद लूपस से पीड़ित लोग

लूपस बीमारी से पीड़ित लोगों को अत्यधिक सक्रिय प्रतिक्षा प्रणाली होने के बावजूद जीवाणु संक्रमण से निजात पाने में समस्या पेश आ सकती है। मेरी टीम और मैंने पाया कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि पुरानी और निरंतर रहने वाली सूजन ऐसे लोगों की प्रतिरक्षा कोशिकाओं को भ्रमित कर देती है। एक अत्यधिक सक्रिय प्रतिरक्षा प्रणाली जीवाणु संक्रमण को नियंत्रित करने में विफल क्यों हो सकती है, इसे समझने के लिए हमने न्यूट्रोफिल पर ध्यान केंद्रित किया। न्यूट्रोफिल ऐसे सफेद रक्त कोशिकाएं होती हैं जो शरीर में जीवाणु के प्रवेश करने पर सबसे पहले प्रतिक्रिया करती हैं। न्यूट्रोफिल डीएनए और रोमाणुरोधी प्रोटीन छोड़ सकते हैं, जिन्हें न्यूट्रोफिल एक्सट्रासेलुलर ट्रैप या 'नेट्स' कहा जाता है। ये नेट्स जीवाणु (बैक्टीरिया) को जकड़कर उनके फैलाव को सीमित कर सकते हैं और उन्हें मार सकते हैं। वैज्ञानिक अवसर इन ट्रैप को एक समान मानते हैं, लेकिन शरीर अलग-अलग तरीकों से नेट्स बना सकता है, और वे सभी एक समान रूप से प्रभावी नहीं होते। उदाहरण के लिए, 'स्टैफिलोकोक ऑरियस' नामक बैक्टीरिया शरीर पर हमला करता है तो नेटेट्स नाम का एक रसायन छोड़ता है। इसके बाद न्यूट्रोफिल एक जाल बनाता है, जो जीवाणुरोधी प्रोटीन से भरपूर होता है।

कांग्रेस के कृत्य भी याद करें राहुल

राहुल गांधी ने तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव-चिहन पर चुनाव आयोग की अंतरिम रोक के बाद भाजपा और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पहले शिवसेना, फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और अब तृणमूल कांग्रेस हर बार एक ही तरीका अपनाया गया: पार्टी तोड़ी गई, चुनाव-चिहन पर कब्जे की लड़ाई खड़ी हुई और जनता के जनदेश को पलटने का प्रयास हुआ। उन्होंने इसे “वोट चोरी, सरकार चोरी और अब पार्टी चोरी” की भाषा में व्यक्त किया। चुनाव आयोग का पक्ष अलग है। आयोग का कहना है कि तृणमूल के दो प्रतिद्वंद्वी गुटों ने पार्टी के नाम और चुनाव-चिहन पर दावा किया, इसलिए अंतिम निर्णय तक दोनों को मूल नाम और चिहन के उपयोग से रोका गया।

राहुल का आरोप राजनीतिक रूप से तीखा है और इसकी जांच वर्तमान तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए। लेकिन जब कांग्रेस स्वयं विपक्षी दलों की सरकारें गिराने, दलों में विभाजन कराने या जनदेश पलटने की राजनीति का आरोप लगाती है, तब उसके अपने लंबे राजनीतिक इतिहास की समीक्षा भी जरूरी हो जाती है। इतिहास यह बताता है कि भारत में सत्ता की राजनीति, गठबंधन तोड़ने, समर्थन वापस लेने और अनुच्छेद 356 के इस्तेमाल का सिलसिला किसी एक दल तक सीमित नहीं रहा। मगर कांग्रेस का रिकॉर्ड इसलिए विशेष रूप से चर्चा में आता है, क्योंकि उसने चुनावों तक केंद्र की सत्ता संभाली और इसी दौरान अनुच्छेद 356 का सबसे व्यापक इस्तेमाल हुआ। सबसे शुरुआती चर्चित उदाहरण 1959 का केरल है। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और ई.एम.एस. नंबूदरीपाद के नेतृत्व में निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार सत्ता में थी। राजनीतिक आंदोलन और कानून-व्यवस्था के सवालों के बीच केंद्र ने अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल कर सरकार बखास्त कर दी। यह स्वतंत्र भारत में किसी निर्वाचित विपक्षी राज्य सरकार को हटाने के शुरुआती बड़े उदाहरणों में से एक था। उपलब्ध अभिलेख बताते हैं कि नेहरू सरकार 1959 तक अनुच्छेद 356 का छह बार उपयोग कर चुकी थी। इसके बाद इंदिरा गांधी के दौर में राष्ट्रपति शासन का इस्तेमाल कहीं बड़े पैमाने पर हुआ। 1967 से 1969 के बीच ही अनुच्छेद 356 सात बार लगाया गया। 1970 से 1974 के बीच राष्ट्रपति शासन 19 बार लगाया गया। यह वह दौर था जब राज्यों में गैर-कांग्रेसी गठबंधन उभर रहे थे, दल-बदल बढ़ रहा था और कांग्रेस के केंद्रीय वर्चस्व को चुनौती मिल रही थी। लेकिन सबसे उल्लेखनीय घटना फरवरी 1980 की है। इंदिरा गांधी लोकसभा चुनाव जीतकर सत्ता में लौटीं और इसके तुरंत बाद नौ गैर-

कांग्रेसी राज्यों की विधानसभाएं भंग कर दी गईं। ये राज्य थे। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। गुह मंत्रालय के आधिकारिक अभिलेख में भी 17 फरवरी 1980 को इन नौ राज्यों में अनुच्छेद 356 लागू कर विधानसभाएं भंग किए जाने का विवरण दर्ज है।

इतिहास की निष्पक्षता के लिए यह भी जोड़ना जरूरी है कि 1977 में जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने भी सत्ता में आते ही कई कांग्रेस-शासित राज्यों की सरकारें हटाई थीं। 1980 की कार्रवाई को उसी राजनीतिक परंपरा की उलटी प्रतिक्रिया के रूप में भी देखा गया। कांग्रेस के राजनीतिक हस्तक्षेप का एक अलग उदाहरण 1979 का है। चरण सिंह प्रधानमंत्री बने थे और उनकी सरकार



कांग्रेस के बाहरी समर्थन पर निर्भर थी। विश्वास मत से पहले इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाले कांग्रेस समूह ने समर्थन वापस ले लिया। चरण सिंह लोकसभा में बहुमत साबित करने से पहले ही इस्तीफा देने को मजबूर हुए। यह अनुच्छेद 356 का मामला नहीं था, लेकिन समर्थन देकर सरकार बनवाने और फिर समर्थन वापस लेकर सत्ता संकट खड़ा करने का स्पष्ट उदाहरण था। 1989 में कर्नाटक की एस.आर. बोम्मई सरकार की बख्सांगी ने इस पूरे प्रश्न को संवैधानिक मोड़ दिया। केंद्र की कांग्रेस सरकार ने बहुमत खोने की राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की। मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा और 1994 में नौ न्यायाधीशों की पीठ ने ऐतिहासिक फैसला दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति की कार्रवाई न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं है और इस शक्ति का इस्तेमाल केंद्र में सत्तारूढ़ दल के राजनीतिक हितों के लिए नहीं किया जा सकता। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद

काम शुरू करने से महत्वपूर्ण है काम करते रहना



एक प्राचीन कथा के मुताबिक, ब्रह्मा और विष्णु ने शिवलिंग के मस्तक और पैरों की खोज शुरू की। ब्रह्मा को शिव का मस्तक ढूंढने का और विष्णु को शिव के पैर ढूंढने का कार्य सौंपा गया। सभी देवता इसके आरंभ और अंत के विषय में जानने के लिए उत्सुक थे। ब्रह्मा ने अपनी यात्रा आरंभ की और वे आगे बढ़ते गए। कई लोक पीछे छूट गए और कई युग बीत गए। फिर भी ब्रह्मा शिव के मस्तक का पता नहीं लगा पाए। सृष्टि का एक अंत है। सृजन एक बिंदु पर समाप्त होता है। ब्रह्मा ने अपनी यात्रा उसके बाद भी जारी रखी। उन्होंने एक केतकी का पुष्प देखा जो आकाश से नीचे आ रहा था। ब्रह्मा ने केतकी पुष्प से पूछा, ‘तुम कहां से आ रहे हो? क्या तुमने शिव का मस्तक देखा है? यहां से शिव का मस्तक कितनी दूर है?’ केतकी पुष्प ने कहा, ‘मैं शिव के मस्तक से आ रहा हूँ।’ तो ब्रह्मा ने निष्कर्ष निकाला कि शिव का एक मस्तक था और वे पुष्प लेकर नीचे आए। विष्णु का कार्य शिव के पैरों की खोज करना था। ऐसा कहा जाता है कि विष्णु बहुत विनम्र हैं। पालनकर्ता को हमेशा बहुत विनम्र होना चाहिए। रचयिता जैसा भी हो, यदि पालनकर्ता विनम्र हो, तभी पालन कार्य संभव है। व्यवसाय आरंभ करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको व्यवसाय चलाने के लिए बहुत सतर्क, बहुत विनम्र रहना पड़ेगा, अन्यथा व्यापार डूब जाएगा। विष्णु की विनम्रता ने ही उन्हें शिव के चरणों को ढूंढने का कार्य करने योग्य बनाया। युगों तक यात्रा करने के बाद, विष्णु शिव के चरणों को ढूंढने में सक्षम नहीं हुए।

सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचली अदालतों तक लंबित मुकदमों की संख्या बढ़ रही है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या 65 लाख पार कर गई है। इतने बड़ी संख्या ऐसे मामलों की है, जो वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इलाहाबाद और राजस्थान हाई कोर्ट में लंबित मामलों का बोझ बढ़ा है। बंबई, मद्रास, कर्नाटक और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की स्थिति वितानजक है। विडंबना यह है कि हाई कोर्ट का यह बोझ पूरे न्यायिक संकट का केवल एक हिस्सा है। जिला और अधीनस्थ अदालतों में करोड़ों मामले लंबित हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है। एनबीएलटी और विभिन्न न्यायाधिकरण भी मुकदमों के बढ़ते ढ़ाव से जूझ रहे हैं। न्यायी न्याय के हर मंच पर समय की कमी और मामलों की अधिकता एक साथ दिखाई दे रही है।

- संतोष ठाकुर, बिलासपुर

प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंह राव की कांग्रेस सरकार ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकारें बर्खास्त कर दीं। उत्तर प्रदेश में घटनाक्रम अलग था, क्योंकि मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने पहले इस्तीफा दिया था और उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगाया गया। फिर भी 1992-93 की कार्रवाई अनुच्छेद 356 के राजनीतिक इस्तेमाल पर होने वाली बहस का प्रमुख हिस्सा बनी। केंद्र की राजनीति में 1999 का वाजपेयी सरकार प्रकरण अवसर कांग्रेस के खिलाफ उदाहरण के रूप में दिया जाता है। यहां तथ्यों को ठीक क्रम में रखना जरूरी है। संकट तब शुरू हुआ जब जयललिता की अन्नाद्रमुक, जिसके 18 सांसद थे, ने वाजपेयी सरकार से समर्थन वापस लिया। राष्ट्रपति के निर्देश पर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने विश्वास मत मांगा और 17 अप्रैल 1999 को प्रस्ताव 269 के मुकाबले 270 मतों से पराजित हुआ। 2018 के कर्नाटक चुनाव ने गठबंधन राजनीति का नया उदाहरण दिया। भाजपा 104 सीटों के साथ सबसे बड़ा दल बनी, लेकिन बहुमत से आठ सीट पीछे थी। कांग्रेस की 78 और जेडी(एस) की 37 सीटें मिलीं। कांग्रेस ने जेडी(एस) नेता एच.डी. कुमारस्वामी को समर्थन दिया और दोनों दलों ने सरकार बनाई। यह पूरी तरह संवैधानिक चुनाव-बाद गठबंधन था, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से भाजपा ने इसे सबसे बड़े दल को सत्ता से दूर रखने की रणनीति बताया। 2019 के महाराष्ट्र चुनाव में स्थिति और जटिल थी। भाजपा ने 105 और शिवसेना ने 56 सीटें जीतीं। दोनों चुनाव-पूर्व गठबंधन में थे और संयुक्त संख्या स्पष्ट बहुमत से ऊपर थी। राहुल आज “वोट चोरी, सरकार चोरी और पार्टी चोरी” की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का अपना इतिहास भी सत्ता-समीकरण, समर्थन वापसी, अनुच्छेद 356 के इस्तेमाल और चुनाव-बाद गठबंधन की राजनीति से खाली नहीं है। 1959 का केरल, 1980 के नौ राज्य, 1992 की भाजपा सरकारें, 1979 में चरण सवाई, 2018 का कर्नाटक और 2019 का महाराष्ट्र ये सभी घटनाएं इस राजनीतिक इतिहास के दस्तावेज हैं। इसलिए कांग्रेस को पूरी तरह “दूध की धुली” मानना इतिहास के साथ न्याय नहीं होगा। इतिहास किसी एक दल को निर्दोष या दोषी घोषित करने का साधन नहीं होना चाहिए, बल्कि यह याद दिलाने का माध्यम होना चाहिए कि भारतीय राजनीति में सत्ता के लिए गठबंधन, विभाजन, समर्थन-वापसी और संवैधानिक प्रावधानों के राजनीतिक इस्तेमाल की परंपरा पुरानी है और कांग्रेस भी उससे बाहर नहीं रही।

(लेखक हरिभू प्रहकार है, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर आपकी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर देख सकते हैं।



हनुमान अंश की टीम को बधाई

आज नई दिल्ली में बाबा नीब करौरी जी के जीवन पर आधारित फिल्म 'हनुमान अंश' के कलाकारों ने मेट वी। हनुमान जी के प्रति उनकी भावित को खिनाम के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाने के लिए फिल्म की पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाई। -अमित शाह, गृह मंत्री

एसआईआर ने फंसाया एसआईआर केवल वोट चोरी व लोकतंत्र को खत्म करने का औजार ही नहीं है। बल्कि ये एक फ्रेक्टेस्टीन मॉन्स्टर (एक कहानी का किरदार) बन गया है, जिसने अब उसी के लोगों को फंसा दिया है। -मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस अध्यक्ष

हम अपनी द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी में अगले महत्वपूर्ण पड़ाव को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अप्रैल को 'दशहरा' के शुभ अवसर पर लागू होगा। यह न्यूजीलैंड के साथ एक मजबूत और अधिक महत्वाकांक्षी आर्थिक साझेदारी बनाने की हमारी साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। -पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री

रूस के साथ साढ़े दस साल से चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए यह गुलकात बहुत अहम है और इससे बहुत कुछ बदल सकता है। हमने ओमेरि की राष्ट्रपति ट्पू से बात की है। दोनों ने तय किया है कि वे अगले हफ्ते न्यूयॉर्क में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा के सालाना सत्र के दौरान गुलकात करेंगे। -वैलेन्टिनिर जेलेन्स्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति

हमारा पता
हरिभूमि कार्यालय
फ़ोन: २, गौरवराथ, बिलासपुर
रिंग: 401050,271016,फैक्स-271018
ई-मेल: haribhoomi2016@gmail.com
वेब-साइट: **www.haribhoomi.com**



हरिभूमि

छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, हरियाणा व दिल्ली से एक साथ प्रकाशित

समाचार ही नहीं, विचार भी

कर लो दुनिया मुट्ठी में...छत्तीसगढ़ की महिलाओं के हाथों में पांच साल में बढ़े 7.1 फीसदी मोबाइल

हरिभूमि न्यूज ►► रायपुर

किसी जमाने में जब रिम के मोबाइल फोन लॉच हुए थे तो उसके लिए टेगलाइन रखी गई, कर लो दुनिया मुट्ठी में। ये स्लोगन अब से 23 साल पहले काफी चर्चा में रहा। देर-सबेर या करीब द्वाई दशक बाद अब ये लाइन कम से



- राज्य की महिलाओं की डिजिटल पहुंच का दायरा बढ़ा
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं की इस डिजिटल पहुंच का दायरा पिछले कुछ वर्षों में ►►शेष पेज 4 पर

कम छत्तीसगढ़ की महिलाओं के मामले में खरी उतर रही है। दरअसल राज्य में पिछले पांच साल में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाली महिलाओं की संख्या में 7.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं की इस डिजिटल पहुंच का दायरा पिछले कुछ वर्षों में ►►शेष पेज 4 पर

बैंक खाता भी, लेकिन मोबाइल की पहुंच उससे पीछे

महिलाओं की आर्थिक और डिजिटल पहुंच को साथ देखने पर एक और दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। एनएफएस-6 में छत्तीसगढ़ की 15-49 वर्ष की 93.4 फीसदी महिलाओं के पास ऐसा बैंक या बचत खाता है, जिसे वे खुद इस्तेमाल करती हैं। एनएफएस-5 में यह अनुपात 80.3 फीसदी था, यानी बैंकिंग पहुंच के इस संकेतक में 13.1 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई। इसके पीछे ये वजह भी हो सकती है कि राज्य में महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना संचालित है। इस योजना में शामिल होने के लिए महिलाओं के पास बैंक खाता होना जरूरी है।

गांव और शहर की कहानी अलग

डिजिटल पहुंच में सबसे बड़ा अंतर ग्रामीण और शहरी महिलाओं के बीच दिखाई देता है। एनएफएस-6 में छत्तीसगढ़ की 15-49 वर्ष की महिलाओं में अपना मोबाइल इस्तेमाल करने वाली महिलाओं का अनुपात शहरी क्षेत्रों में 71 फीसदी और ग्रामीण क्षेत्रों में 41.5 फीसदी था, यानी दोनों के बीच 29.5 प्रतिशत अंक का अंतर है। एनएफएस-5 में अपना मोबाइल इस्तेमाल करने वाली ग्रामीण महिलाओं का अनुपात 34 फीसदी था, जो एनएफएस-6 में बढ़कर 41.5 फीसदी हुआ। शहरी महिलाओं में यह 61.2 फीसदी से बढ़कर 71 फीसदी हुआ, यानी दोनों क्षेत्रों में वृद्धि हुई, लेकिन ग्रामीण और शहरी महिलाओं के बीच काफी अंतर बना हुआ है।

बलरामपुर में सबसे ज्यादा 169 प्रतिशत, कांकेर में केवल 67 फीसदी

मानसून की विदाई का दौर, 13 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश, सात जिलों में 50 से 80 फीसदी

छत्तीसगढ़ में इस साल मानसून की बारिश लगभग पूरी होने के बाद अब इस मौसम की विदाई की बेला है। राज्य के 33 जिलों में बारिश के आंकड़ों पर नजर डालने से एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है, जो यह बताती है कि बरसात तो जमकर हुई, लेकिन बारिश का वितरण समान

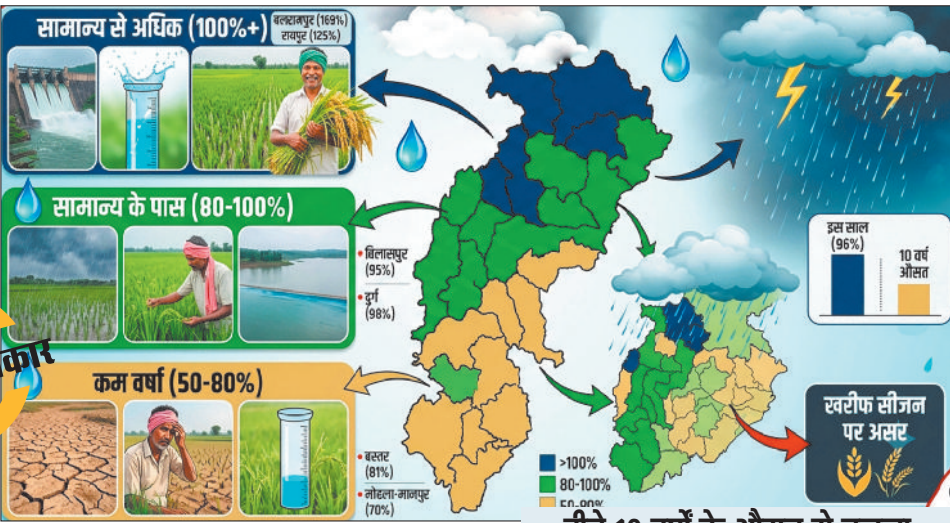
नहीं है। राज्य के 13 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई तो वहीं 7 जिलों में 50 से लेकर 80 फीसदी बारिश हुई है। जाहिर है कि यह बारिश का असमान वितरण है। इसका असर आने वाले समय में खरीफ सीजन की पूरी खेती-किसानी पर नजर आ सकता है।

हरिभूमि न्यूज ►► रायपुर

कृषि विभाग के अनुसार, 21 सितंबर 2026 तक जारी रिपोर्ट के मुताबिक, राज्यभर में इस अवधि में कुल औसत वर्षा 1005.2 मिलीमीटर (मिमी) दर्ज की गई है, जो बीते 10 वर्षों के औसत (1050.8 मिमी) का लगभग 96 प्रतिशत है। प्रदेश के सभी 33 जिलों में बारिश का वितरण अलग-अलग रहा है, जहां कुछ जिलों में पानी की कमी दिखी, वहीं कई जिलों में झमाझम बारिश से रिकॉर्ड बने हैं।

किस संभाग और जिले में क्या रही स्थिति?

50 से 80 प्रतिशत वर्षा वाले जिले 7 जिले : राज्य के 7 जिलों में मानसूनी बारिश 50.1 से 80 प्रतिशत के बीच सिमट कर रह गई। इनमें सरगुजा (76%), जशपुर (80%), कबीरधाम (81%), मोहला-मानपुर (70%), बमेतरा (74%), बस्तर (81%), कोंडागांव (81%), सुकमा (71%) और बीजापुर (74%) जैसे जिले शामिल हैं।



80 से 100 प्रतिशत वर्षा वाले जिले (13 जिले)

प्रदेश के 13 जिलों में बारिश का यह आंकड़ा 80.1 से 100 प्रतिशत के बीच यानी सामान्य के करीब दर्ज किया गया। इसमें कोरिया (96%), बिलासपुर (95%), रायगढ़ (87%), सक्ती (95%), कोरबा (96%), गैरला-पेण्ड्रा (90%), दुर्ग (98%), राजनांदगांव (93%), खैरागढ़ (91%), दंतवाड़ा (88%), कांकेर (67%), और सरगुजा संभाग के कुछ अन्य हिस्से शामिल हैं।

तीन साल की सजा का भी प्रावधान

फर्जी सिम, आईएमईआई से छेड़छाड़ पर 50 लाख जुर्माना

नई दिल्ली। अगर आपके नाम पर कोई सिम कार्ड जारी है और आप उसे किसी दूसरे व्यक्ति को इस्तेमाल करने के लिए देते हैं, तो अब आपको सावधान रहने की चेतावनी दी है। दूरसंचार विभाग ने 21 सितंबर को नई एडवायजरी जारी की है। इसमें कहा है कि फर्जी आईडी से सिम खरीदने या बेचने पर या मोबाइल के आईएमईआई नंबर से छेड़छाड़ करने पर 3 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। दूरसंचार विभाग की चेतावनी सिर्फ सिम कार्ड किसी दूसरे व्यक्ति को देने तक सीमित नहीं है। विभाग ने फेक डॉक्यूमेंट्स, धोखाधड़ी या किसी दूसरे व्यक्ति की पहचान का इस्तेमाल करके सिम हासिल करने से भी बचने को कहा है। इसके अलावा अपने नाम पर जारी सिम को बेचने, ट्रांसफर करने या किसी ऐसे व्यक्ति को देने से भी बचना चाहिए, जो इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। खास तौर पर साइबर फ्रॉड के लिए इस्तेमाल होने वाले 'म्यूल सिम' से जुड़ना यूजर के लिए कानूनी परेशानी खड़ी कर सकता है।

कियाए पर सिम देने पर नूल ग्राहक भी फंसेगा

दूरसंचार विभाग ने साफ कर दिया है कि अगर आप अपने नाम से सिम खरीदकर किसी और को बेचते हैं, कियाए पर देते हैं या साइबर ठगी के लिए इस्तेमाल होने देते हैं, तो पुलिस केस और कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ भी होगी। इसके अलावा फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाकर सिम लेना, पहचान छिपाकर धोखाधड़ी करना या किसी और के नाम की सिम का गलत इस्तेमाल करना भी गंभीर अपराध है।

यूपी से केरलम पहुंचा था गिरोह

फ्लाइट से चोरी करने पहुंचे चोर, 11 धरे गए

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मेरठ और बागपत के रहने वाले इस गिरोह के सदस्य हवाई जहाज से सफर कर केरलम पहुंचे थे। केरल में चोरी की बड़ी वारदातों को अंजाम देने आए उत्तर प्रदेश के एक शातिर अंत र रा ज्यी य गिरोह को पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर दबोच लिया है। कोचि, त्रिशूर और कन्नूर पुलिस की संयुक्त टीमों ने कार्रवाई करते हुए 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।



आईएमईआई नंबर बदलने को लेकर भी चेतावनी

दूरसंचार विभाग ने मोबाइल फोन के आईएमईआई नंबर और दूसरे टेलीकॉम आईडेंटिफायर से छेड़छाड़ को लेकर भी चेतावनी दी है। आईएमईआई हर मोबाइल फोन की पहचान से जुड़ा एक यूनिक नंबर होता है। इसे बदलने या छेड़छाड़ करने की कोशिश दूरसंचार अधिनियम की धारा 42 के तहत अपराध हो सकती है। इसी तरह कॉलिंग लाइन आईडेंटिफिकेशन यानी सीएलआई को बदलने वाले दल या तरीकों का इस्तेमाल भी प्रतिबंधित है। इन प्रावधानों के तहत अपराध के लिए 3 साल तक की जेल, 50 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

अपने नाम पर जारी नंबरों की ऐसे करें जांच

सबसे जरूरी बात यह है कि यूजर अपने नाम पर जारी सभी मोबाइल नंबरों की जांच करें। इसके लिए सरकार के संचार सांथी पोर्टल और ऐप में 'नाऊ मोबाइल कनेक्शन इन यूजर नेम' सुविधा उपलब्ध है। यहां आप देख सकते हैं कि आपके नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शन एक्टिव हैं। अगर कोई ऐसा नंबर दिखाई देता है जिसे आपने नहीं लिया है या जिसकी जरूरत नहीं है, तो उसे रिपोर्ट करने की सुविधा भी मौजूद है।

हरिभूमि न्यूज ►► नई दिल्ली

भारतीय सेना के टी-72 और टी-90 टैंकों की ऑपरेशनल क्षमता को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 586 करोड़ रुपए का बड़ा करार किया है। इस करार के तहत इन दोनों टैंकों के लिए स्वदेशी ऑक्जिलरी पावर यूनिट यानी एपीयू खरीदे जाएंगे। एपीयू टैंक की कई अहम प्रणालियों को बिजली उपलब्ध कराने का काम करता है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, स्वदेशी एपीयू को शामिल करने से सेना की मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन की तैयारियों, विश्वसनीयता और लंबे समय तक संचालन की क्षमता को मजबूती मिलेगी। रक्षा मंत्रालय ने 21 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में एक्ज्यूटिव ►►शेष पेज 4 पर

लोकेशन डेटा का गलत इस्तेमाल

गूगल पर 46.3 करोड़ डॉलर का लगा जुर्माना

डबलिन। गूगल पर उपयोगकर्ताओं के लोकेशन डेटा को उचित तरीके से नहीं संभालने के कारण यूरोपीय संघ के सख्त निजता नियमों के उल्लंघन के लिए 46.3 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया गया है। आयरलैंड के डेटा संरक्षण आयोग ने कहा कि जांच में पाया गया कि गूगल ने 'वेब एंड ऐप एक्टिविटी' सेटिंग में उपयोगकर्ताओं के लोकेशन डेटा का कानून के अनुरूप और निष्पक्ष तरीके से प्रसंस्करण नहीं किया।



यूरोपीय संघ का चौथा जुर्माना

आयरिश डेटा संरक्षण आयोग के उपयुक्त ग्राहम डॉयल ने कहा, लोकेशन डेटा लोगों के लिए फायदेमंद होने के साथ गूगल को अलावा बड़ा सकता है, लेकिन इससे किसी व्यक्ति के बारे में काफी जानकारी भी सामने आ सकती है।

जैतूसाव मठ का मामला

पुजारी भगवान की संपत्ति का स्वतंत्र मालिक नहीं बन सकता

हरिभूमि न्यूज ►► बिलासपुर

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने श्री ठाकुर रामचंद्र जी स्वामी जैतूसाव मठ पब्लिक ट्रस्ट, रायपुर की संपत्तियों के राजस्व रिकॉर्ड में कलेक्टर का नाम मैनेजर/सर्वकार के रूप में दर्ज किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। याचिकाओं का अंतिम फैसला नही हुआ है। यदि सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष याचिकाकर्ता अपना अधिकार साबित करता है तो ►►शेष पेज 4 पर



पांच साल से अधिक की देरी से दाखिल हुई याचिका

हाईकोर्ट ने कहा कि राजस्व प्रविष्टि से ट्रस्ट के प्रबंधन अथवा सर्वकार पद पर याचिकाकर्ता के अधिकार का अंतिम फैसला नही हुआ है। यदि सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष याचिकाकर्ता अपना अधिकार साबित करता है तो ►►शेष पेज 4 पर

586 करोड़ की डील, टैंकों में लगेंगे स्वदेशी पावर यूनिट

टी-72 और टी-90, जंग के मैदान में बिना आवाज करेंगे शिकार

हरिभूमि न्यूज ►► नई दिल्ली

भारतीय सेना के टी-72 और टी-90 टैंकों की ऑपरेशनल क्षमता को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 586 करोड़ रुपए का बड़ा करार किया है। इस करार के तहत इन दोनों टैंकों के लिए स्वदेशी ऑक्जिलरी पावर यूनिट यानी एपीयू खरीदे जाएंगे। एपीयू टैंक की कई अहम प्रणालियों को बिजली उपलब्ध कराने का काम करता है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, स्वदेशी एपीयू को शामिल करने से सेना की मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन की तैयारियों, विश्वसनीयता और लंबे समय तक संचालन की क्षमता को मजबूती मिलेगी। रक्षा मंत्रालय ने 21 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में एक्ज्यूटिव ►►शेष पेज 4 पर

टी-72 और टी-90 टैंकों में एपीयू का काम क्या होगा

एपीयू टैंक में बिजली पैदा करने का एक वैकल्पिक स्रोत है। इसका इस्तेमाल फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सॉफ्ट और वन स्टेशनलाइजेशन सिस्टम जैसी महत्वपूर्ण प्रणालियों के लिए किया जाता है। इसके अलावा टैंक की दूसरी सहायक प्रणालियों को भी एपीयू से बिजली मिल सकती है। इन प्रणालियों के लगातार और असोमंद तरीके से काम करने के लिए बिजली की जरूरत होती है। ऐसे में एपीयू टैंक की संचालन क्षमता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।



कशर से सेना को क्या फायदा

स्वदेशी एपीयू को टैंकों में शामिल करने से भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन की ऑपरेशनल रेंजिंस मजबूत होगी। साथ ही टैंकों की विश्वसनीयता और अस्टोनेबिलिटी यानी लंबे समय तक प्रभावी तरीके से काम करने की क्षमता में सुधार होगा।

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता

इस करार को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया गया है। मंत्रालय के अनुसार, यह मेक-2 व्यवस्था के तहत उद्योग के नेतृत्व में शोध और विकास से तैयार तकनीक को वास्तविक रक्षा उत्पादन तक पहुंचाने का उदाहरण है। इसका मतलब है कि देश में विकसित तकनीक केवल परीक्षण या विकास तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उसे सेना के इस्तेमाल के लिए उत्पादन और शामिल करने की प्रक्रिया में लाया जा रहा है। इससे महत्वपूर्ण रक्षा प्रणालियों में घरेलू क्षमता मजबूत करने में मदद मिलेगी।

ख़बर संक्षेप

आईओसी के 425 किमी लंबी पाइप लाइन को मंजूरी



नई दिल्ली। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के निदेशक मंडल ने केरल के कोच्चि को तमिलनाडु के तूतीकोरिन से जोड़ने वाली 424.65 किलोमीटर लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के निर्माण और संचालन के लिए 2,448.70 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दे दी है। कंपनी ने सूचना में यह जानकारी दी।

मुम्बई की चॉल में रहकर ऑटो चालक पिता ने कोटा कोचिंग में पढ़ाया, अब जौनपुर का प्रभात बनेगा डॉक्टर



कोटा। कैरियर एवं कोचिंग सिटी कोटा लगातार सामाजिक बदलाव की कहानिया लिख रहा है। गांव-कस्बों की ऐसी प्रतिभाएं जो श्रेष्ठ मार्गदर्शन के अभाव में सपने पूरे नहीं कर पाती थीं। कोटा उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा रहा है। ऐसा ही एक और उदाहरण सामने आया है जौनपुर के प्रभात का। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो इस सफलता पर परिवार की खुशियां बयां कर रहा है। बेटे की सफलता की खबर

ओरिएंटल इंश्योरेंस डिजिटल सेवाओं पर करेगी निवेश

नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी डिजिटल सेवाओं को मजबूत करने और ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए अगले तीन साल में करीब 500 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बना रही है। 'प्रीद्योगिकी को मजबूत करने के लिए हमारे पास अपने संसाधनों हैं और इसके लिए बजट भी रखा गया है। हमें इसमें कोई समस्या नहीं होगी। अगले तीन साल में कुल खर्च करीब 500 करोड़ रुपये होगा।' उन्होंने कहा कि कुछ आरएफपी (प्रस्ताव के लिए अनुरोध) पहले ही जारी किए जा चुके हैं और बाकी परियोजनाओं पर अगले दो साल में काम शुरू किया जाएगा।

भारतीय बैंकों के लिए नकदी की उपलब्धता बढ़ी : एसएंडपी

एजेंसी ► नई दिल्ली

वित्तीय शोध और साख़ निधारित करने वाली एजेंसी एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने सोमवार को कहा कि अमेरिकी डॉलर आकर्षित करने के लिए विशेष जमा योजना के तहत जुटाई गई 127 अरब डॉलर की राशि भारतीय बैंकों के लिए 'बड़ी राहत' है। इससे वित्तपोषण की तंग स्थिति आसान हुई है और नकदी की उपलब्धता बढ़ी है। बैंकों ने आठ जून से 31 अगस्त, 2026 के बीच विदेशी मुद्रा प्रवासी-बैंक (एफसीएनआर-बी) खातों के लिए रिफॉर्ड 127 अरब डॉलर की जमा राशि जुटाई। एसएंडपी ने कहा कि यह राशि 31 मार्च, 2026 तक बैंकों में जमा राशि का करीब 4.5 प्रतिशत है।

रेटिंग एजेंसी ने कहा, "भारतीय बैंकों को इससे बड़ी राहत मिली है। अनुकूल दरों ने देश के प्रवासी समुदाय को बड़ी मात्रा में जमा राशि वापस भारत भेजने के लिए प्रेरित किया। हम इसे व्यापक रूप से सकारात्मक मानते हैं।" एसएंडपी ने कहा, "इससे वित्तपोषण की तंग स्थिति सुगम हुई है। पिछले चार साल से कर्ज वृद्धि, जमा वृद्धि से अधिक रही है।"

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए जून की शुरुआत से अगस्त के बीच इन तीन से पांच साल की अवधि वाली जमाओं की मूल राशि से जुड़ी जोखिम लागत को स्वयं उठाया है।

जमाओं की अवधि तीन से पांच साल है

एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स की ऋण विश्लेषक गीता चुध ने कहा, "एफसीएनआर (बी) जमाओं की अवधि तीन से पांच साल है। इससे बैंकों की वित्तपोषण की स्थिति में सुधार होगा और परिसंपत्ति-देनदारों की अवधि के अंतर को पाटने में मदद मिलेगी।" उसने कहा कि बैंकों की कुल परिसंपत्तियां इन खातों के जरिये जुटाई गई 127 अरब डॉलर की राशि से भी अधिक बढ़ सकती हैं।

रुपया 15 पैसे की बढ़त के साथ 95.81 प्रति डॉलर

मुंबई। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और वैश्विक स्तर पर जोखिम लेने की धारणा में सुधार के बीच अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया सोमवार को 15 पैसे मजबूत होकर 95.81 (अस्थायी) प्रति डॉलर पर रहा। बाजार में अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत की उम्मीद से भी धारणा बेहतर हुई। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और अमेरिका-ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत की उम्मीद से रुपया मजबूत हुआ। घरेलू शेयर बाजारों में तेजी और अमेरिकी बॉण्ड पर प्रतिफल में नरमी ने भी रुपये को समर्थन दिया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 95.86 प्रति डॉलर पर खुला।

प्राश्य - 01

कार्यालय खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कटघोरा जिला-कोरबा छ.ग.

कमांक/लेखा/निविदा/2026-27/2633

कटघोरा दिनांक 21/09/2026

निविदा सूचना

वि.ख. कटघोरा जिला-कोरबा छ.ग. मे सिकल सेल एनीमिया टेस्टिंग एवं स्क्रीनिंग शिविर करने हेतु इच्छुक अनुभवी स्त्र. सहायता समूह/रजिस्टर्ड फर्म /संस्था से प्रति ईकाई मे स्वयं के संसाधनो से टेस्टिंग एवं स्क्रीनिंग शिविर करने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। विस्तृत नियमावली, निविदा प्रपत्र दिनांक 21.09.2026 से 05.10.2026 तक शाम 05:00 कार्यालयीन समय मे प्राप्त एवं जमा (पंजीकृत डाक द्वारा) कर सकेंगे। निविदा खुलने की तिथि 06.10.2026 को शाम 04:00 बजे निर्धारित है।

खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कटघोरा जिला- कोरबा छ.ग.

यूपीआई पर अभी कुछ और साल शुल्क नहीं लेना चाहिए : नीति आयोग

एजेंसी ► नई दिल्ली

नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने सोमवार को सरकार को सुझाव दिया कि उसे कम से कम कुछ और वर्षों तक यूपीआई लेनदेन पर शून्य शुल्क की व्यवस्था जारी रखनी चाहिए और उसके बाद इसकी समीक्षा करनी चाहिए। कुमार ने कहा कि वह किसी भी मूल्य के यूपीआई लेनदेन के लिए कारोबारियों से शुल्क लेने के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को यूपीआई को व्यापक सकारात्मक प्रभाव वाला सार्वजनिक उपक्रम मानना चाहिए।

नकदी की और लौटने की संभावना

कुमार ने कहा, "यह कदम नकदी के इस्तेमाल की ओर वापस लौटने की बहुत बड़ी संभावना पैदा करता है। छोटे से शुल्क से भी इस प्रतिगामी व्यवहार को बढ़ावा मिलेगा। कुमार ने कहा, "फिलहाल अच्छी व्यवस्था को जारी रखने के लिए यथास्थिति बनाए रखना बेहतर होगा।"

यूपीआई छह साल तक पूरी तरह शुल्क मुक्त रहा

सरकार ने करीब छह साल तक पूरी तरह शुल्क-मुक्त रहे यूपीआई भुगतान में बदलाव करते हुए 15 सितंबर को घोषणा की थी कि 15 अक्टूबर से इस मंच के जरिये कारोबारियों को 2,000 रुपये से अधिक के भुगतान पर 0.4 प्रतिशत शुल्क लगाया जाएगा। हालांकि, रोजमर्रा के व्यक्ति-से-व्यक्ति (पी2पी) लेनदेन और छोटे भुगतान को शुल्क से बाहर रखा गया है।



वाहकों को कोई शुल्क नहीं देना होगा : वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा था, "यूपीआई के जरिये ऐसे भुगतान करने पर वाहकों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।" मंत्रालय ने कहा था कि एमडीआर (मवेट डिस्कॉन्ट रेट) कारोबारी भुगतान व्यवस्था के भीतर लगाया जाने वाला शुल्क है और यह यूपीआई भुगतान करने वाले वाहकों पर नहीं लगाया जाएगा।

एमडीआर शुल्क वाहकों से नहीं लिया जाएगा : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर 'फजीत खबर' फैलाने का आरोप लगाया था और कहा था कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि एमडीआर शुल्क वाहकों से नहीं लिया जाएगा।

विपक्ष ने अमेरिकी दबाव में आने की बात कही थी

मंत्रालय ने यह भी कहा था कि व्यक्तियों के लिए यूपीआई का उपयोग 'बिना किसी मासिक सीमा, मात्रा संबंधी प्रतिबंध या शुल्क-मुक्त लेनदेन पर किसी स्तर की सीमा के बिना जारी रहेगा। इस फैसले की विपक्षी दलों ने तीखी आलोचना की थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि यह अमेरिकी दबाव के आगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एक बार फिर आत्मसमर्पण करने की कार्रवाई है।

बुनियादी ढांचे को बनाए रखने जरूरी है

कुमार ने कहा, "इसके कुल लाम सार्वजनिक कोष पर यूपीआई बुनियादी ढांचे को बनाए रखने के लिए पड़ने वाली 20,000 करोड़ रुपये की लागत से कहीं अधिक है। कुमार ने कहा, "इसलिए, कम से कम कुछ और वर्षों तक यूपीआई लेनदेन पर शून्य शुल्क जारी रखना चाहिए, जब तक कि मुद्रा से जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में कुछ गिरावट का रुख दिखाई न दे। उसके बाद स्थिति की समीक्षा की जा सकती है।"

बीएमसी छत्तीसगढ़ कैंसर कॉन्वलेव में 500 से ज्यादा विशेषज्ञ जुटे



रायपुर। बालको मेडिकल सेंटर (बीएमसी) के चौथे छत्तीसगढ़ कैंसर कॉन्वलेव का शुभारंभ शनिवार को नया रायपुर स्थित मेकंजर लेक रिजॉर्ट में हुआ। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कॉन्वलेव के दौरान सर्वाधिकल कैंसर उम्मीलन कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया भी मौजूद रहे। 18 से 20 सितंबर तक चले इस कॉन्वलेव में देश-विदेश के 500 से अधिक कैंसर विशेषज्ञ, चिकित्सक और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। इनमें 11 अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ भी शामिल हैं। कैंसर उपचार में संतुलन की पुनर्स्थापना विषय पर आयोजित कॉन्वलेव में स्तन, स्त्री रोग और मूल-जनन तंत्र के कैंसर के उपचार पर विशेषज्ञों ने चर्चा की। वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर उपचार के विकल्प चुनने, मरीज-केंद्रित इलाज, किफायती स्वास्थ्य

सेवाओं और कैंसर की रोकथाम पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में 20 से अधिक विशेषज्ञ पैनल चर्चाएं, सजीव सैकिकल प्रदर्शन और व्यावहारिक कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

सर्वाधिकल कैंसर मुक्त राज्य बनाने प्रयास : सीएम

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सर्वाधिकल कैंसर की रोकथाम संभव है और छत्तीसगढ़ को सर्वाधिकल कैंसर मुक्त बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बीएससी के वार्षिक कॉन्वलेव को कैंसर उपचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बताया। कैंसर उपचार में योगदान के लिए डॉ. रवि कक्कन को वेदावती अखिल ओरिशन अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। बीएससी की मेडिकल डायरेक्टर डॉ. भावना सिरोही और कंसल्टेंट सैकिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. दिवाकर पांडे ने भी कैंसर रोकथाम और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप शोध के महत्व पर विचार रखे।

छूट से आसान हुआ बजट, क्रेडाई प्रॉपर्टी एक्सपो के अंतिम दिन भी बंपर बुकिंग

प्लॉट, फ्लैट और स्वतंत्र मकानों की रही मांग



छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष पंकज लाहोटी, चेयरमैन मृणाल गोलछा, सचिव अभिषेक बछावत और प्रोग्राम चेयरमैन अशोक मूंदड़ा ने बताया कि एक्सपो में अलग-अलग बजट और जरूरत के अनुसार प्रॉपर्टी के विकल्प उपलब्ध कराए गए। उनका कहना है कि रजिस्ट्री और स्टाम्प ड्यूटी में 50 फीसदी छूट से खरीदारों को आर्थिक राहत मिली।

एक ही जगह कई प्रोजेक्ट्स की जानकारी : एक्सपो में अविनाश ग्रुप, रहेजा ग्रुप, वॉलफोर्ट, क्लासिक, भारद्वाज, रजत, श्री स्वास्तिक, अष्टविनायक, आरती ग्रुप, सिंघानिया बिल्डकॉन, आनंदम, समृद्धि, वीजीआर, पार्यनियर होम्स, सुधि, वुड्स एस्टेट, वीवी टावर, वर्धमान, आरसीपी, ओम एक्सोटीका, चैतन्य ग्रुप, कृष्णा, टू डेवलपर्स, मोनिका रियल बिल्डकॉन, वेदांता विहार और मोक्ष वार्पा समेत कई बिल्डर्स ने अपने प्रोजेक्ट्स प्रदर्शित किए।

मनीव्यू का 1,092 करोड़ का आईपीओ 24 को खुलेगा



नई दिल्ली। डिजिटल ऋण मंच मनीव्यू लिमिटेड 24 सितंबर को अपना 1,092 करोड़ रुपये का आरंभिक सार्वजनिक निगम (आईपीओ) लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने सोमवार को बताया कि आईपीओ के लिए 32 से 34 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का मूल्य दायरा तय किया गया है। ऊपरी मूल्य दायरे पर कंपनी का मूल्यांकन करीब 6,000 करोड़ रुपये है। यह आईपीओ 28 सितंबर को बंद होगा तथा कंपनी के शेयरों को एक अक्टूबर को एनएसई और बीएसई पर सूचीबद्ध किया जाएगा। मनीव्यू के आईपीओ के तहत 750 करोड़ रुपये मूल्य के नए शेयर जारी किए जाएंगे।

भारतीय रिज़र्व बैंक

संपदा कक्ष, रायपुर

वास्तुकारों और ठेकेदारों/ आपूर्तिकर्ताओं के पैनलीकरण हेतु आवेदन आमंत्रित करने की सूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक, रायपुर या आस-पास के स्थानों पर स्थापित वास्तुकारों और ठेकेदारों/ आपूर्तिकर्ताओं की फर्मों से विभिन्न कार्यों हेतु 31 मार्च 2029 तक की अवधि के लिए पैनलीकरण हेतु मुहरबंद आवेदन आमंत्रित करता है। पूर्ण विवरण हेतु तथा रिक्त आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.rbi.org.in पर 'टेंडर अनुभाग' पर जाएं। सुचारु रूप से भरे गए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर, 2026 (14:00 बजे) है।

ध dhan

PUBLIC NOTICE

BEWARE OF FRAUDSTERS IMPERSONATING "DHAN", ITS DIRECTORS AND EMPLOYEES

RAISE SECURITIES PRIVATE LIMITED (formerly known as Moneylicious Securities Private Limited), operating under the brand name "Dhan", is a SEBI-registered stockbroker (SEBI Registration No. IN2000006031), member of BSE, NSE and MCX and a Depository Participant (SEBI Registration No. IN-DP-289-2016) with CDSL operating from Unit No. 2201, 22nd Floor, Gold Medal Avenue, S.V. Road, Beside Patel Petrol Pump, Piramal Nagar, Goregaon West, Mumbai - 400104.

We have become aware of fraudsters unlawfully impersonating Dhan, its directors, employees and representatives and misusing the Dhan name, logo, photographs and brand identity through fake websites, mobile applications, social media accounts, WhatsApp/Telegram groups and other channels.

These fraudsters may falsely offer guaranteed returns, assured profits, IPO allotments, investment opportunities, trading services or other financial benefits, and may induce the public to transfer money or disclose OTPs, passwords, banking, trading or other confidential information.

Dhan does not authorise any person, group, platform or third party to collect money from the public in the name of Dhan, its directors or employees, or to promise guaranteed/assured returns or profits.

The names and identities of Dhan's directors, including Mr. Jayprakash Gupta and Mr. Pravin Jadhav, have also been misused by fraudsters.

DO NOT TRANSFER MONEY OR SHARE YOUR OTP, PASSWORD, PIN, BANKING OR TRADING CREDENTIALS with any person claiming to represent Dhan. Dhan communicates with its clients only through its official channels:

Website: <https://dhan.co/>
Dhan Web: <https://login.dhan.co/>
Dhan Android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dhan.live>
Dhan IOS: <https://apps.apple.com/in/app/dhan-share-market-trading-app/id1575318726>
Dhan Option Trader: <https://dhan.co/options-trader-web/>
Dhan Option Trader Android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dhanoptions.live>
Dhan Option Trader IOS: <https://apps.apple.com/in/app/options-trader-fno-stocks/id1601444691>
Facebook: <https://www.facebook.com/DhanHQ/>
Instagram: <https://www.instagram.com/dhanhq/>
X: <https://x.com/DhanHQ>; <https://x.com/dhancares>
YouTube: <https://www.youtube.com/@DhanHQ>; <https://www.youtube.com/@InvestingwithDhan>; <https://www.youtube.com/@CommoditiesbyDhan>; <https://www.youtube.com/@AlandAlgosbyDhan>; <https://www.youtube.com/@DhanHQMalayalam>; <https://www.youtube.com/@DhanHQTelugu>; <https://www.youtube.com/@DhanHQMMarathi>; <https://www.youtube.com/@DhanHQQannada>; <https://www.linkedin.com/company/Dhanhq/>
WhatsApp: <https://whatsapp.com/channel/0029Vb5CCIZJ93wewl6tK638>
Telegram: <https://t.me/JoinDhan>
Dhan Community: <https://madefortrade.in/>

Please note that all official communications from Dhan will be sent only from the @dhan.co domain. If you receive any communication claiming to be from Dhan but sent from @dhan.co, @dhan.co.in, or any other domain, please treat it as suspicious and report it immediately to help@dhan.co.

Persons who have suffered financial loss should immediately report the matter to the appropriate cybercrime/law-enforcement authorities.

Dhan / Raise Securities Private Limited and its group companies shall not be responsible or liable for any loss arising from dealings with unauthorised or fraudulent persons, entities, platforms or groups impersonating Dhan or its directors, employees or representatives.

On Behalf of Raise Securities Private Limited
Sd/-
Manish Garg Compliance Officer

सार्वजनिक सूचना		
ICICI Bank पंजीकृत कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक टावर, चकली सर्किल के पास ओल्ड वादरोड - 390007 कोरियाट नगराचरम : आईसीआईसीआई बैंक टावर, वादा-कुली कॉम्प्लेक्स, मुंबई - 400051		
खर्च नीलामी एवं आमंत्रण सूचना		
मौखे उल्लिखित ऋणधारक (ओं) को आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड से लिए गए सौने के आमूखों की नीलामी 22 अक्टूबर, 2026 को आयोजित की जाएगी। यदि ऋणधारक की मृत्यु हो गई है, तो सभी निमज और तंत उनके सगीति देव उत्तराधिकारी (ओं) पर लागू होगी।		
ऋण खाता संख्या	ऋणधारक का नाम	नीलामी शाखा का पता
शाखा का नाम : भिलाई नगर - भिलाई-3	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, वरगंवादा, खीस लेन जीई रोड, भिलाई-3, जिला - दुर्ग, छत्तीसगढ़ - 490021	
741857000079	राजल मुरुखर	
शाखा का नाम : विहरी	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, रक्षा पहाड़, हल्द्वारी, विमिरी, कोरिया जिला, छत्तीसगढ़। - 497451	
162557000132	गजल रीय कोर	
शाखा का नाम : होरागढ़	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, मकान नं. 233/2जे, मेन रोड, होरागढ़, राजनगरगढ़, छत्तीसगढ़ - 491661	
837157000011	केसारी देवीन	
शाखा का नाम : जगदलपुर	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, तस्मण ऐल्यू, गंधी के पास, वासनी गढ़, जगदलपुर बस्तर जिला, छत्तीसगढ़ - 494001	
108562000977	चुरेद पटेल	
शाखा का नाम : जगदलपुर	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, रम्पेया वार्ड नंबर 18, चिकुट रोड, डिक्कानगर, जगदलपुर, जिला : बस्तर, छत्तीसगढ़ - 494001	
443157000026	अग्रिया वेम	
शाखा का नाम : कांकेर, छत्तीसगढ़	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, न्यू बस स्टैंड के पास, जगदलपुर मेन रोड, कांकेर, छत्तीसगढ़ - 494334	
371757000247	अपेक्ष साहू	
शाखा का नाम : कच्छेर	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, देमसाल गार्ड फॉर्मेशन, दुधमन नंबर 223, वार्ड नंबर 3, मेन रोड, कच्छेर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ 495445	
328862001293	देवमन्दरी	
शाखा का नाम : महारामपुर	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, र. रसिवासर गुल्ल बजट, रेडरोड रोड, महारामपुर छत्तीसगढ़ - 493445	
084105003922	जगदीश सिंह मकड़	
शाखा का नाम : नारायणपुर	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, खसरा नंबर 405/3, मेन रोड, महारामपुर, नारायणपुर - 494661, छत्तीसगढ़	
783557000063	गोसा गेटा	
783557000113	बुद्धी मरकम	
शाखा का नाम : धारवाड़नगर	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, जेएस कॉम्प्लेक्स, भुल्ल वस्तेर, रसगढ़ रोड, धारवाड़नगर, जिला : जगसूर, छत्तीसगढ़ - 496118	
782157000079	योगा जितिल	
शाखा का नाम : रामपुर - भद्रगढ़	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, भागावाग, रामपुर, छत्तीसगढ़ - 492001	
472305000163	शिविन कुमार	
शाखा का नाम : रामपुर - लाम्ही	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, गेज नंबर 1,2,3 गेटो हेव्वा, गेट जेडिबार्ग खुल्ल गेट, अली विहार, लाम्ही, रामपुर, छत्तीसगढ़ - 492006	
478157000029	अनय लालनग	
शाखा का नाम : रामपुर - बल	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, शोभारम प्लाजा ब्रॉकिंग प्लाजा के सामने।विहारनगर रोड, गेटा, रामपुर, छत्तीसगढ़ - 492001	
427857000095	विक्टर सिंह रामपुरसिंह	
शाखा का नाम : रामपुर- कलामंडी	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, ग्रांड रोड, गेटा रोड, कलामंडी बैंक, रामपुर, छत्तीसगढ़ - 492001	
4388570000087	केदार नरनरनगला कुमारी	
शाखा का नाम : राजनगरगढ़	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, खंडेलनरम कॉम्प्लेक्स, प्लॉट नंबर 156/1234, नई बैंक, राजनगरगढ़, छत्तीसगढ़ - 491441	
062405003088	मधुसूत सिंह मुंतिन	
शाखा का नाम : सरगवल्ल	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, मेन रोड, बस स्टैंड के पास, सरगवल्ल 492558, छत्तीसगढ़।	
783257000177	गोमनाथ पटेल	
शाखा का नाम : तिन्वा	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, मुरुखर कॉम्प्लेक्स, बनिवाचारा, रेडरोड रोड, तिन्वा, जिला : रामपुर, छत्तीसगढ़ - 493174	
794857000133	काका कुमर खंडे	
शाखा का नाम : कोरागुमरुड	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, राम कोरागुमरुड, बर्ली कोरागुमरुड, जिला नरसंरुप, अरुनिया 764061	
277362000683	कुसा मर वल्ले	

नीलामी उपरोक्त नीलाम में उल्लिखित वत और विधि पर आयोजित की जाएगी। समय - दोपहर २:०० बजे से शाम ६:०० बजे तक। कृपया ध्यान दें कि आईसीआईसीआई बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के नीलामी की विधि/स्थान/तरीके में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इच्छुक पक्ष नीलामी के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए उपर्युक्त शाखाओं में जा सकते हैं।
दिनांक : 22.09.2026
स्थान : रामपुर, बस्तर, महेद्वार-चिरमिरी-भरतपुर, उत्तर बस्तर कांकेर, दुर्ग, कोरबा, जगसूर, महारामपुर, नारायणपुर, सुकमा, राजनगरीयांव
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता कुने, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड

Dr. Juneja's®

पेट सफा

Natural Laxative Granules & Tablets

कब्ज से राहत

गैस से छुटकारा

एसिडिटी से आराम

गजब का फायदा

अगर आप भी कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसी परेशानियों से घिरे हुए हैं, तो आज ही लीजिए, आयुर्वेदिक पेट सफा ग्रेन्यूल्स। यह पहले दिन से असर दिखाता है, मुंह में चिपकता नहीं और इसकी आदत भी नहीं बनती।

पेट सफा... तो हर रोग दफा

24x7 Helpline: 91197 88888
www.petsaffa.com

Clinically Tested
Trusted by millions

भारत का वो गांव, जहां बच्चों से लेकर बूढ़े तक बोलते हैं अंग्रेजी

कोलकाता। भारत में गांवों की अपनी-अपनी अलग पहचान होती है। कोई गांव अपनी खेती के लिए मशहूर है, तो किसी की पहचान वहां के खान-पान, कारीगरी या किसी खास परंपरा से होती है। कुछ गांव ऐसे भी हैं जो अपनी अनेखी खूबियों की वजह से देशभर में चर्चा में आ जाते हैं। पश्चिम बंगाल का कालियाचक भी ऐसा ही एक गांव है, जिसकी पहचान किसी किले, मंदिर या पर्यटन स्थल से नहीं, बल्कि अंग्रेजी भाषा से जुड़ी है। सौचिए, किसी गांव की गली से गुजरते हुए आपको बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक अंग्रेजी में बातचीत करते लोग सुनाई दें। कहीं घर के अंदर ट्यूशन चल रही हो, तो कहीं कोई आईईएलटीएस की तैयारी कर रहा हो। सुनने में थोड़ा अलग लगता है, लेकिन कालियाचक में अंग्रेजी से जुड़ा ऐसा ही माहौल देखने को मिलता है।

अंग्रेजी ने बनाई अलग पहचान
पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में स्थित कालियाचक को अंग्रेजी शिक्षकों और ट्यूशन सेंटरों के लिए जाना जाता है। यहां अंग्रेजी सिर्फ स्कूल की किताबों तक सीमित नहीं है। कई परिवारों के लिए यह पढ़ाई के साथ-साथ रोजगार का भी जरिया बन चुकी है। गांव की गलियों में आपको छोटे-छोटे ट्यूशन सेंटर और होम क्लास मिल जाएंगे। कहीं बच्चे स्पोर्ट्स इवेंट्स सीखते नजर आते हैं, तो कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं और आईईएलटीएस जैसी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। कालियाचक की खास बात यह है कि यहां अंग्रेजी सिखाने का काम कई परिवारों में पौढ़ियों से आगे बढ़ता आया है।



गांव से दिल्ली-मुंबई और विदेश तक पहुंच

कालियाचक के अंग्रेजी शिक्षकों की पहुंच सिर्फ आसपास के इलाकों तक सीमित नहीं है। यहां से कई शिक्षक दिल्ली, मुंबई और बंगलुरु जैसे बड़े शहरों में भी काम करने जाते हैं। कुछ लोग विदेशों में भी शिक्षण से जुड़े काम करते हैं, जबकि कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए विदेशी छात्रों को पढ़ाते हैं। यानी जिस गांव की गलियों में कभी पढ़ाई की छोटी-छोटी क्लास शुरू हुई, वहीं से निकलकर कुछ लोगों ने देश और विदेश तक अपना कैरियर बना लिया है।

बच्चों को घर से मिलता है अंग्रेजी का माहौल
कालियाचक में अंग्रेजी सीखने का माहौल सिर्फ ट्यूशन सेंटरों तक सीमित नहीं है। कई माता-पिता बच्चों को घर पर भी अंग्रेजी में बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। स्थानीय स्तर पर बच्चों के लिए डिबेट और दूसरी शैक्षणिक गतिविधियां भी आयोजित की जाती हैं। इसका फायदा यह होता है कि बच्चों को अंग्रेजी सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि बातचीत के एक माध्यम के तौर पर सीखने का मौका मिलता है।

सिर्फ अंग्रेजी ही नहीं, खेती और कारोबार भी पहचान

हालांकि, कालियाचक की चर्चा अंग्रेजी शिक्षकों और ट्यूशन सेंटरों की वजह से होती है, लेकिन गांव की अर्थव्यवस्था सिर्फ इसी पर निर्भर नहीं है। यहां खेती-बाड़ी और स्थानीय कारोबार भी लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा है। मालदा क्षेत्र अपने आम और लीची के लिए भी जाना जाता है। इसके अलावा रेशम और जूट से जुड़े छोटे कारोबार भी कई परिवारों की आजीविका का हिस्सा हैं। यानी कालियाचक की कहानी सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले लोगों की कहानी नहीं है। यह उस गांव की कहानी है, जहां एक हुनर धीरे-धीरे कई परिवारों के लिए पढ़ाई, रोजगार और आगे बढ़ने का जरिया बन गया।

रोचक खबरें

अमेरिका में 100 साल बाद खोजी गई बिल्ली की नई प्रजाति

वॉशिंगटन। 100 साल से भी ज्यादा समय के लंबे इंतजार के बाद, वैज्ञानिकों ने बिल्ली की एक नई प्रजाति खोजी है, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। यह दिखने में बिल्कुल किसी खूंखार तेंदुए जैसी है, लेकिन उसका वजन आम पालतू बिल्ली से भी कम है। सिर से लेकर पूंछ के अंत तक, सिर्फ 18 इंच लंबी इस बिल्ली को साइंटिस्ट्स ने लियोपार्डस तिलकायो नाम दिया है। इन सवालों का जवाब दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया की एक कहानी से मिलता है। साल 2017 में वहां एक स्थानीय शख्स को सड़क किनारे जंगल में एक बिल्ली का बच्चा मिला था। उसने उसे कोई आम पालतू बिल्ली समझकर घर में रख लिया। लेकिन, एक साल तक पालने के बाद जब उसे एहसास हुआ कि यह पूरी तरह से एक जंगली जीव है, तो उसने इसे सेंडा वडें एनिमल रिफ्यूज नाम की एक स्थानीय संस्कृत्युओं को सौंप दिया।

सुअर की किडनी के सहारे 271 दिनों तक जिंदा रहा इंसान

वॉशिंगटन। मेडिकल साइंस के इतिहास में एक ऐसा अभूतपूर्व चमत्कार हुआ है, जिसने किडनी की बीमारी और अंगों की किल्लत से जूझ रहे दुनिया भर के लाखों मरीजों के लिए उम्मीद की नई किरण जगा दी है। अमेरिका में 66 वर्षीय टिम एंड्रयू नाम के एक मरीज को सुअर की किडनी के सहारे 9 महीनों तक जिंदा रखा गया। उस मरीज को आनुवंशिक रूप से संशोधित सुअर की किडनी के सहारे पूरे 9 महीने यानी 271 दिनों तक बिना डायलिसिस के जिंदा रखा गया। महत्वपूर्ण बात ये है कि इस दौरान वो सामान्य जिंदगी जीए और जब इसके बाद उन्हें इंसानों वाला किडनी लगा दिया गया। यह अभी तक के मेडिकल इतिहास में अब तक का सबसे लंबा समय है, जब किसी जानवर का अंग किसी इंसान के शरीर में इतने लंबे वक्त तक सफलतापूर्वक काम करता रहा। 'द लॉसेट' जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे खास बात यह रही कि सुअर की किडनी ने एक 'ब्रिज' यानी अस्थायी सहारे के रूप में काम किया।

इसके बाद उन्हें इंसानों वाला किडनी लगा दिया गया। यह अभी तक के मेडिकल इतिहास में अब तक का सबसे लंबा समय है, जब किसी जानवर का अंग किसी इंसान के शरीर में इतने लंबे वक्त तक सफलतापूर्वक काम करता रहा। 'द लॉसेट' जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे खास बात यह रही कि सुअर की किडनी ने एक 'ब्रिज' यानी अस्थायी सहारे के रूप में काम किया।

अमर होने के लिए गर्लफ्रेंड के पीरियड का खून जमा कर रहा अरबपति

वॉशिंगटन। ब्रायन जॉनसन की जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा ऐसे कामों में गुजरता है, जो अमतौर पर लोगों को बहुत अजीब लग सकता है। वह सुबह 4 बजे उठकर 11 बजे तक खाना खा लेते हैं और फिर रात 8 बजे सोने चले जाते हैं। वह हर रोज कई तरह की करीब 100 गोलियां खाते हैं। साथ ही वह अपनी गर्लफ्रेंड के पीरियड्स का खून फ्रीज में जमा कर रहे हैं। यह सब कोशिश या टोटेके उम्र बढ़ने की रफ्तार धीमा करने के लिए है। उनका मकसद मौत को चकमा देना यानी अमर होना है। अमेरिकी अरबपति टेक एंटरप्रेनोर ब्रायन जॉनसन ने अपनी जिंदगी का मकसद मौत को मात देना बना लिया है। 48 साल के जॉनसन दुनिया में सबसे सेहतमंद बनने के लिए जुनूनी हैं और अपनी बायोलॉजिकल उम्र उलटते हुए हमेशा जिंदा रहने की 'अजीब' कोशिश में लगे हैं।

3 डॉलर में खरीदी सफेद कटोरी की 7 साल बाद बदली किस्मत, 18 करोड़ में हुई नीलामी

न्यूयॉर्क। सोचिए, अगर घर में रखा कोई ऐसा ही सामान अचानक करोड़ों रुपए का निकल आए तो? शायद पहली बार में यकीन करना मुश्किल होगा। कुछ ऐसा ही हुआ न्यूयॉर्क के एक परिवार के साथ, जब उनके घर में रखी एक छोटी सी सफेद कटोरी की असली कीमत सामने आई। परिवार ने इस कटोरी को साल 2007 में एक सेल से सिर्फ 3 डॉलर में खरीदा था। भारतीय रुपए में देखें तो उस समय यह रकम करीब 150 से 200 रुपए के आसपास रही होगी। परिवार के लिए यह बस एक खूबसूरत और साधारण चीज कटोरी थी, जिसे उन्होंने घर में सजाकर रख दिया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह छोटी सी चीज करीब 1000 साल पुराना इतिहास अपने अंदर समेटे हुए है। कई साल तक कटोरी घर में ही पड़ी रही। फिर साल 2013 में इसकी नजर कुछ एक्सपर्ट्स पर पड़ी। शुरुआत में माना गया कि इसकी कीमत करीब 2 से 3 लाख डॉलर हो सकती है। लेकिन, जैसे-जैसे इसकी जांच आगे बढ़ी, मामला और दिलचस्प होता चला गया। विशेषज्ञों ने पहचान लिया कि यह कोई आम कटोरी नहीं थी, बल्कि चीन के उत्तरी सांग राजवंश के समय की डिंगवेयर कटोरी थी। उत्तरी सांग राजवंश का शासन

चीन में 960 से 1127 के बीच रहा था। नीलामी में कटोरी की कीमत भारतीय करेंसी में करीब 18 करोड़ रुपए बैठती है।

सफेद दाग

(त्व्युकोडमा) का लेसर द्वारा इलाज

कालदा प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जरी एवं बर्न सेंटर

आर.के.सी. के सामने, जी.ई. रोड, चौबे कालोनी एवं गंगा डाकघर/रेलवे स्टेशन के उपर, कर्तार माल के पास, पंचपेदी नाकर, रायपुर (छ.ग.)

9827143060

Ajay Advt.

सुचश

हॉस्पिटल

24 Hours Helpline

9926386660

कोटा-गुदियारी रोड, रायपुर

Ajay 9827144371

कहां और कैसे करें अप्लाई?
साउथ चाइना मॉनिंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन में युआनलिसरयान शिनशेन और जिनझुआ जैसे कई नए डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गए हैं। यहां लोग अपना रजिस्ट्रेशन और आईडी वैरिफिकेशन कराके खुद की डिजिटल एक्टर प्रोफाइल बनाते हैं। आपकी फीस कितनी होगी, यह पूरी तरह आप पर निर्भर है। ऑर्थोडॉन्सिज फीस 700 रुपए (50 युआन) से शुरू होकर 14.48 लाख रुपए (99,999 युआन) तक जा सकती है।

सऊदी के डूबे जहाज से निकली 16 टन चांदी 82 साल पहले रियाल ले जा रहा था जहाज

रियाद। साल 1994 में अमेरिकी जहाज एसएस जॉन बैरी के मलबे से 10 लाख से ज्यादा सऊदी चांदी के रियाल निकाले गए। यह सिक्के अमेरिकी लिबर्टी जहाज के डूबने के पांच दशक बाद बरामद हुई। ऐसे में इसने साल 1944 में डूबे जहाज की घटना को ताजा कर दिया, जो ओमान के पास अपने होल्ड में 30 लाख चांदी के सिक्कों के साथ डूबा था। मलबे से बरामद की गई चांदी का वजन 16 टन में चांदी आंका गया। हालांकि, इस खोज के बाद भी खजाने को लेकर कई रहस्यों का खुलासा नहीं हो सका है। अमेरिकी जहाज दूसरे विश्व युद्ध के आखिरी सालों में सऊदी अरब के लिए सिक्के ले जा रहा था। ये रियाल सऊदी



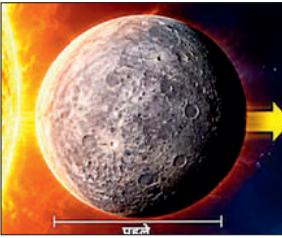
अरब के कहने पर फिलाडेल्फिया (अमेरिका) में ढाले गए थे और इनका मकसद तेजी से बढ़ रहे तेल उद्योग में काम करने वाले मजदूरों को भुगतान करने में मदद करना था। क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर में छपी 1995 की रिपोर्ट के अनुसार, इस कागों को इतना गुप्त रखा गया था कि कू को सिक्कों के बारे में पता ही नहीं था।

चांदी का रहस्य

द क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर ने नवंबर 1995 में रिपोर्ट दी थी कि मिले हुए 10 लाख सिक्कों (16 टन वजन) से कम से कम 2 करोड़ डॉलर मिलने की उम्मीद थी। सोवियत ने कहा कि इन सिक्कों को एक साथ इकट्ठा बेचा जा रहा था, क्योंकि वे जहाज के मलबे से ऐतिहासिक रूप से जुड़े हुए थे। ये सिक्के सऊदी अरब के लिए तब मंगवाए गए थे, जब देश को मजदूरों की भुगतान करने के लिए मुद्रा की जरूरत थी, जिसमें तेल सुविधाओं के निर्माण में तेल मजदूर भी शामिल थे।

किशमिश की तरह सिकुड़ रहा बुध 23 किलोमीटर हो चुका है छोटा

टोक्यो। कल्पना कीजिए, धूप में रखा अंगूर धीरे-धीरे सिकुड़कर किशमिश बन जाए। कुछ ऐसा ही नजारा अंतरिक्ष में हमारे सौरमंडल के सबसे छोटे ग्रह बुध के साथ देखने को मिल रहा है। एक नई स्टडी में वैज्ञानिकों ने पाया है कि बुध ग्रह पहले के अनुमान से कहीं ज्यादा तेजी से सिकुड़ रहा हो सकता है। हफपोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, यह स्टडी जर्मन एयरोस्पेस सेंटर के इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस रिसर्च ने की है। स्टडी के प्रमुख लेखक जापान के गाकु निशियामा हैं। इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों के मुताबिक, बुध का सिकुड़ना पुराने



अनुमान से करीब 30 फीसदी ज्यादा हो सकता है। इसका मतलब है कि इस छोटे से ग्रह के व्यास में अब तक करीब 14 मील यानी 23 किलोमीटर तक की कमी आ चुकी हो सकती है। यह आंकड़ा इसलिए हैरानी वाला माना जा रहा है, क्योंकि बुध का पूरा व्यास यानी सर्किल ही लगभग 4,900 किलोमीटर है।

आखिर सिकुड़ क्यों रहा है बुध?

बुध के सिकुड़ने का वजह उसके अंदर छिपी है। वैज्ञानिकों के अनुसार, करीब 4.5 बिलियन साल पहले बने इस ग्रह का बेहद गर्म लौह कोर धीरे-धीरे ठंडा हो रहा है। ठंडा होने के साथ इसका कोर सिकुड़ रहा है और उसके साथ ग्रह का मेटल और क्रस्ट भी संकुचित हो रहे हैं। इसका असर बुध की बाहरी सतह पर दिखाई देता है। जैसे किसी कपड़े को अंदर से कपड़े पर उसकी सतह पर सिलवटें पड़ जाती हैं, वैसे ही बुध की सतह पर भी सिकुड़ने के कारण बड़ी-बड़ी दरारें और झुर्रियां जैसी संरचनाएं बनी हैं।